वर्ष-7 अंक-6 जून 2017 मूल्य 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

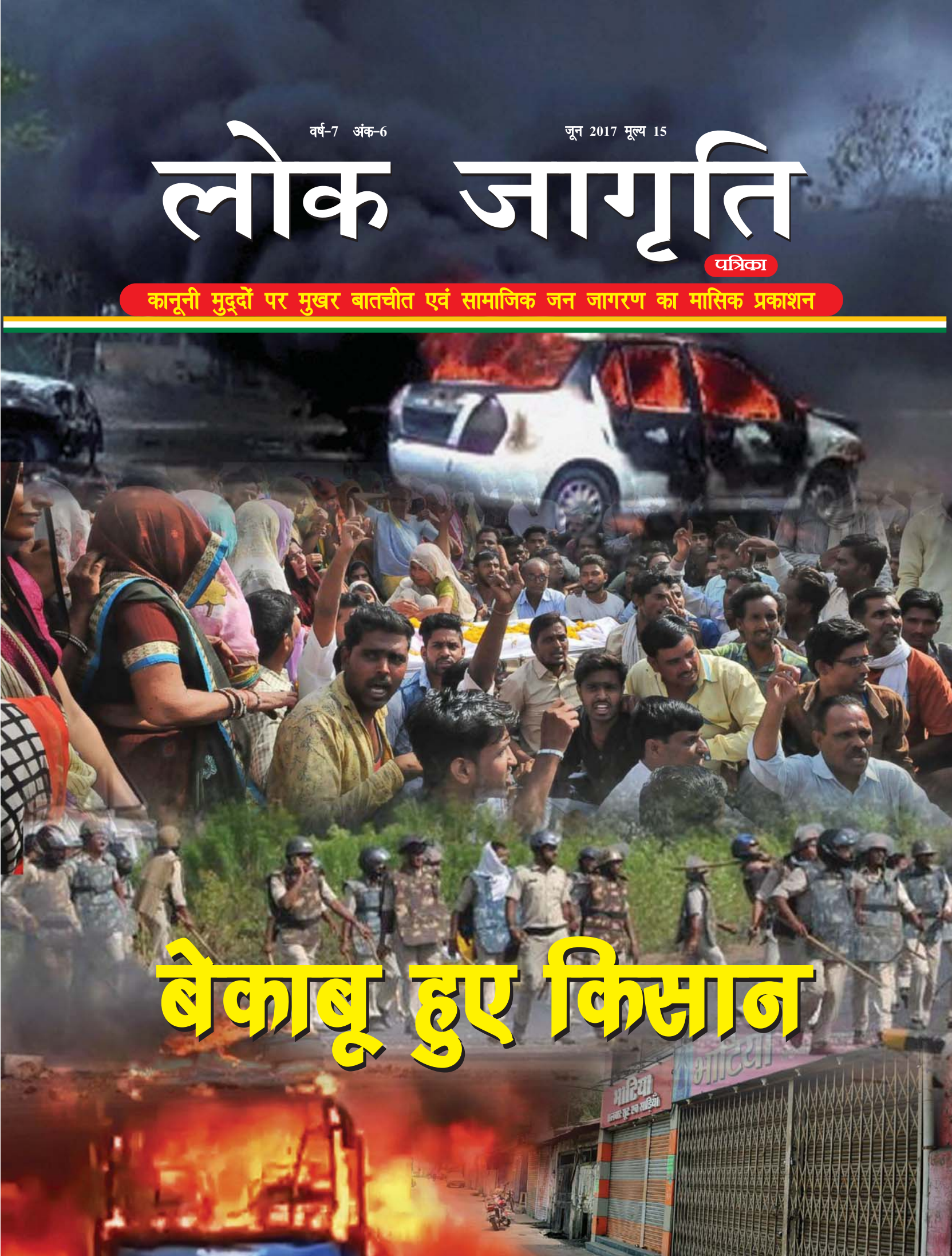

बेकाबू हुए किसान

DPL BUILDERS PVT. LTD

Present's

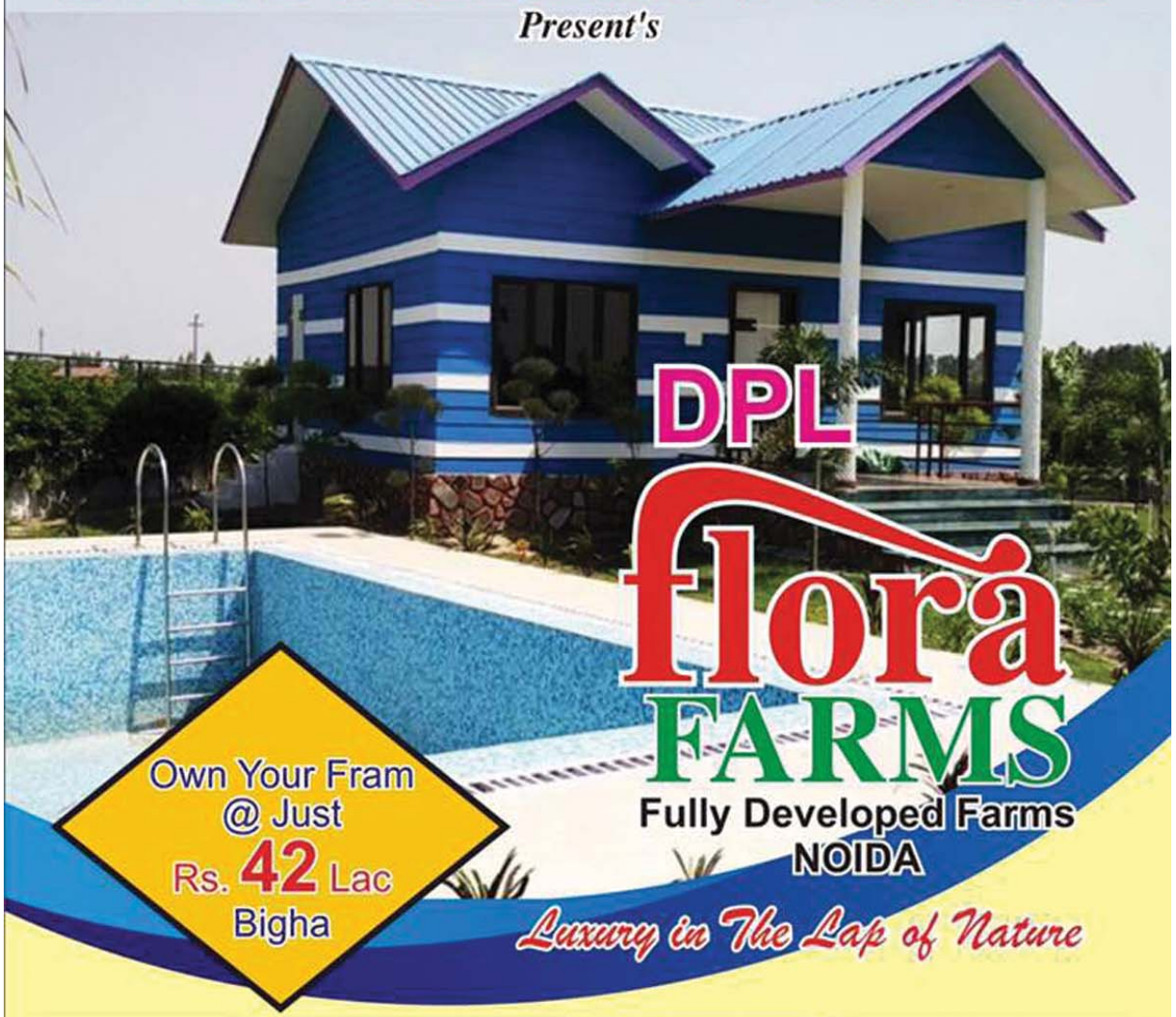

DPL flora FARMS

Fully Developed Farms
NOIDA

Luxury in The Lap of Nature

Own Your Fram
@ Just
Rs. 42 Lac
Bigha

Exotic Ambience | **Beautiful Landscapining** | **Water Bodies** | **Pollution Free Environment**

Swiming Pool

Cricket Ground

Club

Children Zone

Party Lawn

Cafeteria

Horse Riding

Adventure Activities

For Site Visit Contact : A. Sinha +91-7840023993, +91-9818500547

Marketing office : **DPL BUILDERS PVT. LTD** | **B-153, Sector-63, Noida**

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10– सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11– लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12– बड़े नोट 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13– हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14– भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15– समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16– देश के प्राकृतिक संसाधनो पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17– सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18– कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19– गरीबों की सही पहचान और लोगों को रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20– टोल टैक्स समाप्त करना।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैंकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं।लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं ।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारण से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाऐं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.com

Suresh Pandey 9810514888

INDIAN/ FOREIGN BOOKS, JOURNALS,
NEW/OLD LAW BOKS,
BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIER

SK

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4, West Vinod Nagar, Delhi - 110092
E- mail: suresh66pandey@gmail.com
pandeysureshk@gmail.com

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका

95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010
lokjagriti@gmail.com, 9560522777

www.lokjagriti.com

लोकसभा सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह को लोकजागृति पत्रिका भेंट करते संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा एवं बृजमोहन।

जिलाधिकारी कन्नौज श्री जगदीश प्रसाद को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते समाचार संपादक आलोक सोलंकी।

राज्य मंत्री खनन को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते आलोक सोलंकी।

राजीव पांडेय एसडीएम देहात को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते समाचार संपादक आलोक सोलंकी।

धर्म के लिए धन नहीं मन चाहिए।

लोक जागृति पत्रिका

अप्रैल 2017 वर्ष 7 अंक 6

संरक्षक

कपिल सिंघल

डा. ए.जी. अग्रवाल

संपादक

संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल

समाचार संपादक

बृजमोहन

आलोक सोलंकी

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय

विजय बहादुर सिंह

तेज सिंह यादव (एडवोकेट)

नरेन्द्र कुमार सक्सेना

गिरीश त्रिपाठी

एस.बी.एस. गौतम

सत्येंद्र श्रीवास्तव

अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)

आलोक सोलंकी

राहुल मिश्र

जगजीत सिंह

कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)

राजेश कुमार मिश्र

कमल कांत त्रिपाठी (एडवोकेट)

तरुण गुप्ता (एडवोकेट)

पूनम सिंह (एडवोकेट)

शोभा चौधरी

अनिल कुमार शुक्ला

रजनीश कुमार पाण्डेय

महेन्द्र पाण्डेय (एडवोकेट)

प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग

खुशबू वर्मा

कानूनी सलाहकार

अभिषेक शर्मा

साज सज्जा

A.N.R. Creation

7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक

संतोष कुमार मिश्रा

द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

दाता की दास्तान बड़ी खराब है यह हमेशा उपेक्षा का शिकार रहे हैं। देश के विकास को दो तरह के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रहेगा पहला अन्नदाता दूसरा कर दाता। हमारे देश की 60 फीसदी जनसंख्या कृषि पर आधारित है और सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन यहीं से होता है लेकिन यह दिन प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है। इसका प्रमुख कारण सरकारी नीतियां एंव सरकारी लोगों द्वारा इनका शोषण अज्ञानता, शिक्षा का अभाव। दूसरा नंबर आता है करदाता का अब जो कर नहीं देते कृषि नहीं करते हैं उनमें आता है चिकित्सालय, विद्यालय, धार्मिक स्थान, सामाजिक संस्थाएं, सांसद, मंत्री, इत्यादि उन्हें मजे ही मजे है। ज्यादा कुछ नहीं लिख पा रहा हूं कि बहुत से माननीय बहुत नाराज भी हो जाएंगे लेकिन हमारे देश में दाताओं की दास्तान बहुत खराब है उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

भारतीय करदाता : भारतीय करदाता को नीबू की तरह से निचोड़ा जाता है जैसे हम सब नीबू को निचोड़ कर शरबत बनाकर आराम से चुस्की लेकर पीते हैं। नींबू को फेक देते हैं। जरा सोचो जो व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है उसे सिर्फ आश्वासन के नाम पर सड़क, देश की उन्नति तो दिखाई जाती है परंतु यदि उसका व्यापार बंद हो जाए या कोई अनहोनी हो जाए या सरकार से प्रत्यक्ष रुप से कोई लाभ नहीं मिलने वाला उल्टे नोटिस मिलता है कि इनकम क्यों कम दिखाई गई। अभी कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए एक लड़की को करोड़ रुपए ईनाम दिया गया वह भी करदाताओं से वसूली गई रकम से लेकिन किसी करदाता को इस बात का ईनाम या अवार्ड नहीं दिया जाता कि ईमानदारी से कर का भुगतान किया है। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुप से लगभग पचासों टैक्स देता है। कुछ जगह टैक्स से ज्यादा खर्चा टैक्स वसूली पर हो रहा है। देश के करदाताओं द्वारा वसूला गया आधा से ज्यादा पैसा अनउत्पादक मनी फालतू खर्च कर दिया जाता है। जबकि यदि कोई व्यक्ति बीमार है दवा के लिए घर बेचता है तो सरकार उसकी दवा का कोई इंतजाम नहीं कर सकती लेकिन उसके लाभ पर कर वसूली उसके मरने के बाद तक करने का कानूनन इंतजाम कर रखा है। इसी तरह शिक्षा की कहानी है किस किस की बात करुं चारों ओर अन्याय एंव अत्याचार है। लेकिन जो आवाज उठाने वाले लोग हैं वह अपना इंतजाम कर लेते हैं। आवाज उठा नहीं सकते या उठाते नहीं हैं वह लाचारी, बेचारी, बेरोजगारी, बेघर रहते हुए भाग्य भरोसे जिन्दगी काट देते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं यहां जो भी नियम कानून बने हैं उसका 80 फीसद दुरुपयोग ही हो रहा है। शासन एसं प्रशासन सिर्फ समाज के कुछ लोगों को सुविधा एवं सहूलियत देने के लिए बनाए गए हैं। यह गरीबों, बेरोजगारों, लाचार लोगों के लिए कदापि नहीं है। जब सरकार की नीति ही धंधा करना हो जाए तो होता ही यही है। हमारे देश में खरबों रुपया सिर्फ नेताओं के पेंशन, सैलरी, भत्ता एवं सरुक्षा सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। जो कि करदाताओं की गाढ़ी कमाई का हिस्सा होता है। सरकार एवं समाज हमेशा से करदाताओं से चोर की तरह व्यवहार करते हैं जबकि करदाता एवं अन्नदाता दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं सरकार को नाचने गाने खेलने कूदने और अन्य लोगों की अपेक्षा इनको भी सम्मान एवं जरुरत पड़ने पर सहायता देनी चाहिए। राज्यसभा में इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

यदि आप दो खरगोशों के पीछे भागते हैं तो आप किसी को भी नहीं पकड़ पाएंगे।

मंदसौर में किसान उग्र

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद किसानों को मिलने वाले कर्ज माफ करने के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी किसान अपनी–अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए हैं

पीपल्स रिसर्च सोसाइटी से जुड़े योगेश दीवान ने कहा– मंदसौर और मालवा में एक कहावत है कि पग–पग रोटी, डग–डग नीर, मालवा धरती गहन गंभीर, यहां पर कृषि उत्पाद काफी अच्छा रहा है और लोग भी काफी शांत हैं इस पूर लाके में अफीम से लेकर नकदी फसल जैसे आलू, मिर्च, मसाले, लहसुन, प्याज और इस तरह के मसाले होते हैं लेकिन इन सबको समर्थन मूल्य में नहीं लिया जाता है जो किसानों के लिए एक मुद्दा रहा है।

नकदी फसलों पर सरकार समर्थन मूल्य नहीं देती जिससे न ही सरकार इसे खरीदती है न ही इसे मंडी में ला सकती है।

इस इलाके में भूमिगत जल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है और अच्छी काली मिट्टी है जिससे पपीते, आलू, प्याज, लहसुन जैसे कई उत्पाद पैदा होते हैं वहीं मध्यप्रदेश में शिक्षा हासिल कर चुके एक व्यक्ति का कहना है कि 1970 के दशक में यहां पर किसानों ने नकदी फसलें बोना शुरू कर दिया . लेकिन आज नकदी फसलें उगाने वाला किसान काफी परेशान है।

इस इलाके में अफीम की भी बड़े पैमाने पर खेती होती है जिसके लिए आबकारी विभाग के अपने नियम कानून हैं। एक व्यक्ति के मुताबिक किसानों को भूमि अधिग्रहण का नया कानून नागवार गुजर रहा था. मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल भूमि अधिग्रहण के लिए नया कानून बनाया है जिसमें किसानों से जमीन लेने का तरीका काफी सरल हो चुका है जिससे किसानों के हाथ से आसानी से जमीन जा रही थी।वो बताते हैं कि राज्य सरकार मालवा के नीमच और मंदसौर के आसपास औद्योगिक इलाका विक. सित कर रही है जिसका लोग विरोध कर रहे थे।

"सोती रही सरकार" : इस इलाके में लोगों के हिंसक होने का इतिहास नहीं है लेकिन किसान भूमि अधिग्रहण कानून और समर्थन मूल्य जैसी समस्याओं पर नाराजगी के चलते अपना ही उपजाया माल जैसे दूध, फल, सब्जियां सड़कों पर फेंक रहे थे जिस पर मध्य प्रदेश सरकार सोती रही। वहीं एक व्यक्ति का कहना है कि जब किसाना. में अंसतोष उठने लगा था और एक जून से किसानों ने आंदोलन शुरू किया तब सरकार ने सुस्ती दिखाई और किसानों से बातचीत करने के लिए सामने नहीं आई. जिसके बाद अपनी अनदेखी से किसान नाराज थे और उग्र हो गए। एक व्यक्ति का कहना है कि मंदसौर में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिलता रहा है और बीजेपी की सरकार की तरफ से होने वाली अनदेखी से किसान आहत हुए हैं। एक व्यक्ति का कहना है कि वो मंदसौर के किसानों के हिंसक प्रदर्शन से हैरान हैं क्योंकि ये समृद्ध इलाका है और बड़ी संख्या में किसान अच्छी हैसियत रखते हैं उनका कहना है कि इस इलाके में करीब 25 से 30 फीसदी किसान ही गरीबी रेखा के नीचे होंगे या फिर अपना कर्ज चुकाने में मुश्किल महसूस कर रहे होंगे।

एक व्यक्ति का मानना है कि पिछले तीन सालों में अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलने से किसानों की हालत काफी खराब हो गई है. गरीब किसान तो परेशान थे ही लेकिन जो मध्य वर्गीय और उच्च मध्य वर्गीय किसान हैं वो भी ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि उसे मदद की जरूरत महसूस हो रही है।

नोटबंदी ने भी तोड़ी किसानों की कमर? : पिछले साल आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी इसके बाद किसानों पर इसका काफी बुरा असर पड़ने की खबरें आती रहीं।

एक व्यक्ति का कहना है कि मंदसौर में कई किसानों ने उन्हें बताया कि कई बैंकों में किसानों के चेक को कैश होने में आठ–आठ दिन लग गए, नकदी नहीं मिलने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ. इसके बाद सरकार ने बैंकों से किसानों को नकद में ही भुगतान करने को कहा तो बैंकों ने भी नोटों की कमी का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर लिए थे। योगेश दीवान का कहना है कि मंदसौर और मालवा का किसान इतनी बुरी हालत में नहीं है कि वो अपनी खेती अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहा है। उनकी मांग हिंदुस्तान के सभी किसानों की तरह कैश क्रॉप के मूल्य को लेकर हर साल होने वाली जद्दोजहद के समाधान की है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गन्ना किसान से लेकर तंबाकू किसान की तरह मंदसौर के किसानों को हर साल लहसुन, मिर्च, प्याज जैसी फसलों के मूल्य की लड़ाई लड़नी पड़ती है।

साभार : इंटरनेट

बुरी पुस्तकों का पढ़ना जहर पीने के सामान है।

बढ़ती बेरोजगारी और किसान आत्महत्या मोदी सरकार की विफलता

26 मई को मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो रहे हैं। 3 साल यानि 36 महीने। प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनावी सभाओं में मोदी ने एक नारा दिया था...आपने उन्हें (कांग्रेस) 60 साल दिए हमें 60 महीने दो। तो अब मोदी सरकार के पास सिर्फ 24 महीने बचे हैं.उन सभी वादों को पूरा करने के लिए जो देश की जनता से किये गये थे।

अगर मोदी जी के 3 साल के कामक. ाज पर गौर करें..तो अब तक कई ऐसे काम हुए हैं जिसे लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा सकती है। उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन, फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, अटल पेंशन योजना...सरकार के लिए लोगा. के 25 फीसदी युवी बेरोजगार हैं..25 से 29 साल के 17 फीसदी नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। आपको बता दें कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था... लेकिन खुद मोदी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारी दर बढ़कर अब 5 फीसदी हो गई है। बेरोजगारी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की खुदकुशी का है. ..राष्टीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 5650 और 2015 में 8007 किसानों ने खुदकुशी की। पिछले साल नवंबर तक किसानों की खुदकुशी के 200 से ज्यादा मामले सामने आए। मोदी सरकार ने यूपी में रोज सामने आती हैं...एंबुलेंस के अभाव में कहीं कोई पिता बेटे के शव को कंधे पर ले जाता दिखता है ...तो कहीं अस्पताल में स्टेंचर नहीं होने पर मरीज को उसके परिजन घसीटते हुए ऑपरेशन थियेटर ले जाते हैं।

ये बात सही है कि आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस का रहा। अभी मोदी सरकार को सत्ता में आए 3 साल ही हुए हैं...लेकिन मोदी जी ने खुद लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाया था। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बुलेट टेंन, 'स्टार्ट अप इंडिया' योजना ये सभी कानों

' को बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मोदी सरकार अब भी कई मोर्चे पर पिछड़ती दिखाई दे रही है। हम बुलेट टेंन की बात नहीं कर रहे...ना ही नमामि गंगे परियोजना की। मेरी समझ में मोदी सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में जिस एक मोर्चे पर विफल रही है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। अंत. रराष्टीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.77 करोड़ से बढ़कर 1.78 करोड़ होने की आशंका है...यानि इस साल देश में 10 लाख बेरोजगार और बढ़ जाएंगे।

एक रिसर्च के मुताबिक देश में हर साल 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं..लेकिन इनमें से ज्यादातर युवा बेरोजगार रह जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 20 से 24 साल कर्जमाफी कर वहां के 55 लाख किसानों का तो भला कर दिया...लेकिन देश के बाकी राज्यों का क्या होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमें पिछले 3 सालों में कुछ ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला...वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है...लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र से मदद नहीं मिलने की बात कह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो देश में हर 1681 मरीज पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। मोदी सरकार ने देश में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल तो कर दी लेकिन भारत में अब भी 5 लाख डॉक्टरों की कमी है। ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों में किस कदर बदहाली है इसकी तस्वीरें को सुनने में अच्छे लगते हैं...लेकिन पहले युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए... किसानों को साहूकारों से छुटकारा और आम जनता को बुलेट टेंन की जगह सस्ती रेल सेवा। डायनैमिक फेयर के नाम पर रेलवे राजधानी समेत कुछ टेंनों में यात्रियों की जेब काटकर जिस तरह मुनाफा कमाने में लगी है उससे मध्यम वर्ग काफी नाराज है। सुरेश प्रभु ने ऐसी कृपा की है कि अब मेरे जैसा आदमी भी राजधानी में सेकेंड एसी में सफर करने से पहले दो बार सोचता है। सरकार की ओर से जारी आर्थिक सर्वे की मानें तो 2016–17 में भारत की जीडीपी 7 फीसदी से बढ़कर 7.75 फीसदी पहुंच सकती है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है की विकास दर 6 फीसदी रहने का अनुमान है। ■ साभार

किसी की आजीविका की हानि नहीं करनी चाहिए।

खूनी खेल की हद

छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने ऐसे समय में खूनी कार्रवाई की है, जब राज्य सरकार माओवाद पर नियंत्रण पाने के दावे कर रही थी। ऐसा पहले भी हुआ है। जब–जब सरकार ऐसे दावे करने लगती है, नक्सली अपनी मौजूदगी का अहसास कराने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। दूसरी बात यह है कि नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाकों में चौड़ी सड़कें बनने से बौखलाए हुए हैं।

छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के नक्सली प्रभाव वाले 44 जिलों में 5,412 किमी सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर चल रहे कार्य को रोकना भी उनका एक मकसद है। नक्सलियों को पता है कि सड़क बनने से सुरक्षाबलों की आवाजाही आसान होगी। नागरिक सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचने लगेंगी तो वे नक्सल प्रभाव से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि जिस तरह से हमला हुआ और इसमें जितना बड़ा नुकसान हुआ, उससे लगता है कि सुरक्षाबलों से भी चूक हुई है। जंगल में सड़क निर्माण पार्टी को सुरक्षा देने गए जवान कहीं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) में ही तो कोई चूक नहीं कर बैठे। कहा जा रहा है कि नक्सली करीब 300 की संख्या में थे। इतने लोगों के जुटने की सूचना CRPF तक कैसे नहीं पहुंची, यह सवाल भी है। कुछ विशेषज्ञों की राय में माओवाद विरोधी ऑपरेशंस की सबसे बड़ी कमी है केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस में समन्वय का अभाव। राज्य पुलिस को केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ जिस तरह मिल–जुलकर काम करना चाहिए, वह नहीं कर रही है।राज्य पुलिस को थानों–चौकियों से खुफिया जानकारी मिलती रहती है। उसने तत्परता दिखाई होती तो CRPF को सचेत किया जा सकता था। नक्सली समस्या से निपटने को लेकर देश में एक राय नहीं बन पाई है। केंद्र सरकार यह कहकर निश्चिंत हो जाती है कि उसका काम केंद्रीय बल भेजना है, माओवादियों से निपटने का बाकी काम तो राज्य सरकारों का है। जहां तक राज्य सरकारों की बात है तो इस समस्या को सुलझाने के सबके अपने–अपने तरीके हैं। उनमें तालमेल के अभाव से समस्या बिगड़ती जा रही है।जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, यहां तो एक समय माओवादियों से लड़ने के लिए कुछ आपराधिक तत्वों को हथियार सौंप दिए गए थे, जिन्होंने कमजोर लोगों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ अति उत्साही अफसरों के कारण माओवाद नियंत्रण के नाम पर कुछ जगहें पुलिस के आतंक राज के लिए जानी जाने लगीं। इससे निपटने का एक ही तरीका है कि माओवाद प्रभावित इलाकों की जनता के साथ गहरे रिश्ते बनाकर नक्सलियों को अलग–थलग कर दिया जाए। इसके बजाय गेहूं के साथ घुन को भी पीस डालने की नीति माओवादियों के हाथ और मजबूत करने वाली साबित होगी। ■ साभार

नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा

भारत की जनता आतंकवाद के साथ साथ नक्सलवाद की भी वर्षो से शिकार हो रही है। जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में आम जनता के साथ सुरक्षाबलों का खून बहाते हैं वहीं दूसरी ओर सुकमा जैसे जंगल और आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद विदेशी सहायता से भारत में लाल आतंक को बढ़ा रहा है। भारत के अनेक राज्यों में अपनी ताकत को बढ़ाते हुए नक्सलवाद ने भारत की अंदरूनी सुरक्षा को भी कमजोर कर दिया है भारत में सेना और सुरक्षाबलों को यदि पूर्ण रूप से आजादी के साथ काम करने की छूट दे दी जाये तो शायद नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में कुछ ही दिन लगेंगे। लेकिन जहां कश्मीर में महबूबा सरकार ने सुरक्षाबलों और सेना के हाथ बांध रखे हैं। वहीं नक्सलवाद प्रभावित इलाको में राजनीतिक दलों और गुटबाजी के चलते सुरक्षाबल नक्सलवाद पर कारवाई नहीं कर पाते हैं। आदिवासी और अनपढ़ ग्रामीण नक्सलवाद के शिकार होते हैं और उनकी मदद से सेना और सुरक्षाबलों पर हमला किया जाता रहा है। वही कश्मीर में भी पत्थरबाजों को राजनीतिक मदद और सरकार का उदासीन रवैया सुरक्षाबलों को सीधी करवाई से रोकता है। जहां पत्थरबाजों की मदद से आतंकवादी बच निकलते हैं वहीं दूसरी और नक्सलवादी और लाल आतंकवाद आदिवासियों की आड़ में सुरक्षाबलों को घेर कर शिकार करते हैं। अंत में सेना और सुरक्षाबलों को आतंक और नक्सलवाद पर सीधी करवाई करते हुए राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज करना होगा और आतंकवाद और नक्सलवाद से सेना और सुरक्षा बलों के जवानो की रक्षा के लिए सुरक्षित योजना बनानी होगी वही राजनैतिक दलों को भी देश हित के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ■ साभार

आप अपने मन में जैसा अपने बारे में सोचे हैं वैसे ही बन जाते हैं।

पत्थरबाजों का हौसला बढ़ाने वाले नेताओं से होती है निराशा

दो अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैशनल हाईवे पर देश की सबसे बड़ी रोड टनल का उद्घाटन करते हुए कहा था कि यह केवल जम्मू और कश्मीर की दूरी कम करने वाली सुरंग नहीं विकास की लम्बी छलांग है और कश्मीर के युवा को अब टैरेरिज्म और टूरिज्म में से किसी एक को चुनना होगा। जवाब फारूख अबदुल्ला ने दिया, ''मोदी साहब से कहना चाहता हूँ कि बेशक टूरिज्म यहाँ की जीवन रेखा है लेकिन जो पत्थर बाज हैं उन्हें टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो अपने देश के लिए पत्थर फेंक रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है।''

अभी कुछ दिन पहले सीआरपीएफ के जवानों के साथ कश्मीरी युवकों के हिंसक होने का वीडियो सामने आया था जिसमें जवानों ने हथियारों से लैस होने के बावजूद बेहद संयम का परिचय दिया। सेना और सरकार इन पत्थर बाजों की परवाह नहीं कर रही होती तो आत्मरक्षा के तहत इन पत्थर बाजों को ऐसा माकूल जवाब इन जवानों से अवश्य मिल गया होता कि भविष्य में कोई और कश्मीरी युवक पत्थर मारने तो क्या उठाने की हिम्मत भी नहीं करता लेकिन अगर जवानों की तरफ से इन पत्थर बाजों को जवाब नहीं दिया जा रहा तो केवल इसलिए कि हमारी सरकार इन्हें अपना दुश्मन नहीं अपने देश के ही नागरिक मानती है लेकिन यह लोग हमारे जवानों को क्या मानते हैं?

अबदुल्ला साहब से इस प्रश्न का उत्तर भी अपेक्षित है कि कश्मीर के नौजवानों को टूरिज्म से मतलब नहीं है यहाँ तक तो ठीक है लेकिन उन्हें टैरेरिज्म से मतलब क्यों है और आप जैसे नेता इसे जायज क्यों ठहराते हैं?

एक तरफ आप सरकार से कश्मीर समस्या का हल हथियार नहीं बातचीत के जरिए करने की बात करते हैं लेकिन कश्मीर के युवा के हाथों में बन्दूकें लिए टूरिज्म से ज्यादा टैरेरिज्म को चुनें तो आपको सही लगता है? शायद इसलिए कि आपकी राजनीति की रोटियाँ इसी आग से सिक रही हैं। यह कहाँ तक सही है कि हमारे जवान हथियार होते हुए भी लाचार हो जाएं और कश्मीर का युवा पत्थर को ही हथियार बना ले? यह इस देश का दुर्भाग्य है कि बुरहान जैसे आतंकवादी अपने ही देश के मासूम लोगों की जानें लेकर गर्व से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और वहाँ के यूथ आइ. कान बन जाते हैं लेकिन हमारे जवान किसी पत्थर बाज को आत्मरक्षा के लिए गाड़ी की बोनट पर बैठा कर पुलिस थाने तक भी ले जाते हैं तो इन पत्थर बाजों के मानवाधिकारों की दुहाई दी जाती है और सेना से सफाई माँगी जाती है।

अगर पत्थर बाज अपने देश के लिए पत्थर फेंक रहे हैं तो हमारे जवान किसके लिए पत्थर और गोलियाँ खा रहे हैं? अगर देश को पत्थर बाजों को समझने की जरूरत है तो क्या आपको देश और जवानों के सब्र को समझने की जरूरत नहीं है? अबदुल्ला साहब का कहना है कि आप लोगों को देश की परवाह है लेकिन पत्थर बाजों की नहीं तो क्या आप पत्थर बाजों को इस देश का हिस्सा नहीं मानते? हाल के चुनावों में वो कौन लोग थे जिन्होंने बन्दूक की नोंक पर कश्मीरी आवाम को वोट डालने से रोका? कश्मीर के युवा हाथ में बन्दूकें या पत्थर लेकर इस मुद्दे का हल चाह रहे हैं? यह तो कश्मीर के युवा को ही तय करना होगा कि वह और कब तक कुछ मुठ्ठी भर नेताओं के हाथों की कठपुतली बने रह कर अपनी उस जन्नत में बारूद की खेती करके उसे जहन्नुम बनाना चाहता है या फिर डल झील की खूबसूरती और केसर की खुशबू से एक बार फिर पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है।

■ साभार : पीएस

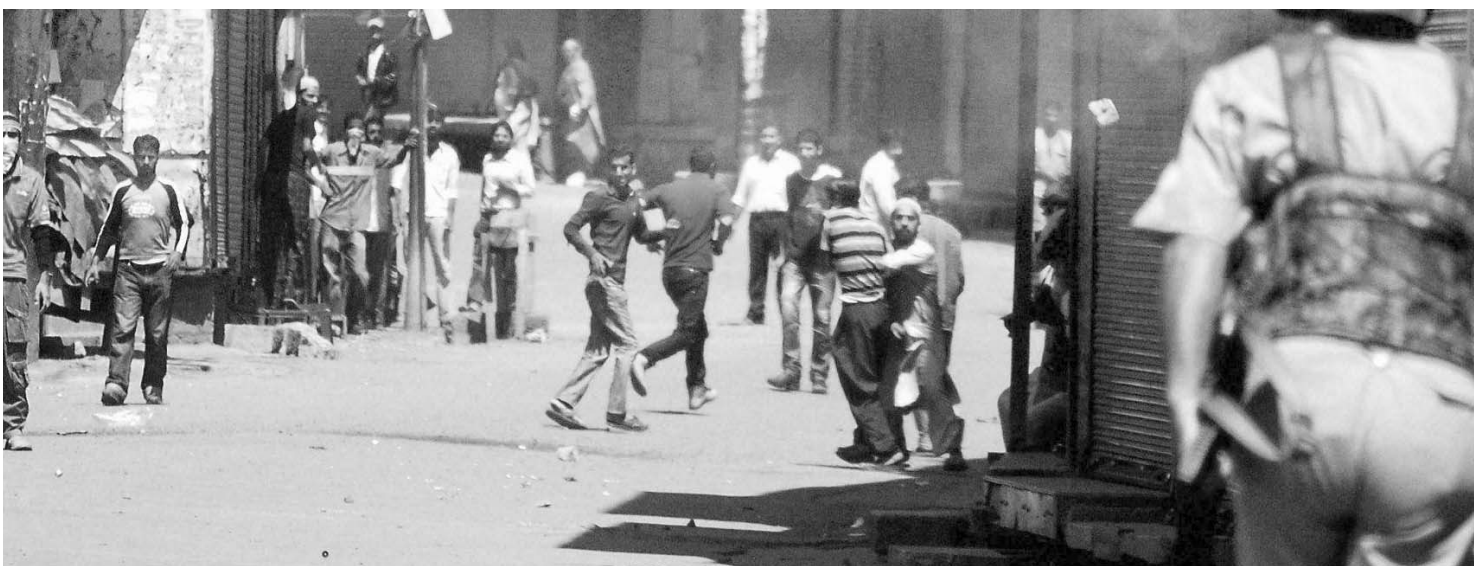

वर्तमान की चिंता करिए भविष्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा

जमानत का अधिकार

देश की जेलों में फैसले का इंतजार करते विचाराधीन कैदियों की विशाल संख्या लंबे समय से चिंता का कारण बनी हुई है। समय–समय पर उपयुक्त मंचों से यह चिंता जाहिर भी होती रही है। मगर इस संख्या को कम करने का कोई ठोस उपाय नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर लॉ कमिशन इस बारे में कोई पहल करता है तो इसे वक्त की जरूरत ही कहा जाएगा। खबरों से संकेत मिलता है कि लॉ कमिशन ने सरकार को भेजी गई अपनी सिफारिशों में जमानत को आसान बनाने पर खास ध्यान दिया है। इसके मुताबिक सात साल तक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में आरोपी अगर सजा की अवधि का एक तिहाई हिस्सा या ढाई साल जेल में काट चुका है तो उसे जमानत दे दी जानी चाहिए। ऐसे ही सात साल से ऊपर की सजा के प्रावधान वाले ऐसे मामलों में, जिनमें मृत्य दंड अपेक्षित नहीं है, आरोपी अगर सजा की अवधि का आधा हिस्सा जेल में गुजार चुका है तो उसे बेल दे दी जानी चाहिए। इसके अलावा भी कई सुझाव लॉ कमिशन ने अपनी फेहरिस्त में शामिल किए हैं। जैसे यह कि ट्रायल कोर्ट में किसी आरोपी की जमानत की अर्जी पेश किए जाने के एक हफ्ते के अंदर उस पर फैसला हो जाना चाहिए। लॉ कमिशन के मुताबिक हाईकोर्टों को इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाकर इसे अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसे सुझावों पर न्यायिक हलकों में पहले भी काफी विचार–विमर्श हो चुका है। विचाराधीन कैदियों की समस्या लंबे समय से देश की न्याय व्यवस्था की कुशलता पर सवालिया निशान लगाए हुए है। ऐसे कैदियों की संख्या भी अच्छी–खासी है जो अदालत से जमानत पा जाने के बावजूद जेलों से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि अपने लिए जमानतदार जुटाना उनके बूते की बात नहीं है। लॉ कमिशन ही नहीं, इंसाफ के तकाजों को समझने वाला कोई भी व्यक्ति कहेगा कि किसी शख्स की गरीबी को उसके जेल में पड़े रहने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी समस्याएं सिर्फ सिफारिशों से हल नहीं होतीं। जरूरी है कि सरकार इन सिफारिशों की आत्मा तक पहुंचे और जल्द से जल्द इन पर अमल सुनिश्चित करे।

योगी आदित्यनाथ कैसे दूर करेंगे कुपोषण

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण के आंकड़े भी आ गए. इन आंकड़ों को पहले जारी किया जाता, तो हो सकता था कि ये चुनावी चर्चा का विषय बने होते, तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार का अच्छा–बुरा काम दिखाते. अखिलेश का जो हुआ, सो हो गया, अब देश में सबसे ज्यादा चर्चा में मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं. अब उनके सामने चुनौती होगी कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जो तस्वीर सामने आई है, उसका वह क्या और कैसे करने वाले हैं...? सबसे बड़ी चुनौती तो उनके राज्य में बच्चों के कुपोषण को लेकर सामने आई है. यह बताती है कि देश में बिहार के बाद सबसे ज्यादा ठिगने बच्चे उत्तर प्रदेश में ही हैं. रिपोर्ट यह भी बताती है कि एक साल तक के बच्चों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर है. अब देखना होगा कि शाकाहार को बढ़ावा देने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के इस कलंक को कैसे बेहतर पोषण से ठीक करती है...?

■ एजेंसी

अभी 35.7 प्रतिशत भारतीय बच्चों का वजन कम

महेंद्र कुमार पांडेय (एडवोकेट) : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से पूरे देश में कराया जाता है. इस सर्वेक्षण का यह चौथा दौर है. इससे पहले 2006 में इसके तीसरे दौर को पूरा किया गया था. चौथे दौर के लिए सारे राज्यों के नतीजे पहले जारी किए जा चुके थे, केवल उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने आनी बाकी थी. इसमें सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में पांच साल तक के 46.3 फीसदी बच्चे ठिगनेपन का शिकार हैं. इसका मतलब यह होता है कि उनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ती. कुपोषण का एक दूसरा प्रकार उम्र के हिसाब से वजन नहीं बढ़ना है, इसमें भी उत्तर प्रदेश के 39.5 प्रतिशत बच्चे सामने आए हैं, जबकि भारत में अभी 35.7 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं. यानी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औसत से ज्यादा गंभीर स्थिति में है, सो, ऐसे में यह देखना लाजिमी होगा कि योगी सरकार इस मसले पर कितनी गंभीरता से कदम उठाती है. दरअसल स्वास्थ्य का यह मुद्दा सीधे–सीधे पोषण से आकर जुड़ता है. बीजेपी–शासित राज्यों में यह पहले से बहस का विषय रहा है कि सरकारी माध्यमों से पोषण के सस्ते विकल्पों को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं. आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में शिव. राज सिंह चौहान की सरकार ने पिछले साल चार जिलों में कुपोषित बच्चों की सेहत जल्दी ठीक करने के लिए अंडे खिलाने के बने–बनाए प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि इसके लिए जैन संतों का भी दबाव था. भोजन के अधिकार अभियान और कुपोषण दूर करने के लिए अभियान चलाने वाले समूह का मानना था कि अंडा पोषण का सबसे सस्ता और सहज उपलब्ध विकल्प है, लेकिन शिवराज सरकार ने उनकी नहीं सुनी, और इसके बदले आंगनवाड़ी और स्कूलों में सप्ताह में तीन दिन दूध पिलाने की बात कही गई. अलबत्ता अब यहां पर पाउडर वाला दूध ही बच्चों को पिलाया जा रहा है. देश में और अब ज्यादातर राज्यों में जब बीजेपी सत्तासीन है, और उसमें भी एक मुख्यमंत्री पूरी तरह भगवाधारी है, तो यह तो अब संभव होता दिखता नहीं कि लोगों को पोषण का कोई ऐसा विकल्प सरकारी माध्यमों से मिलने वाला है. बूचड़खानों को बंद करने या दूसरी जगह ले जाने की कवायदों ने इस बात को और पुख्ता ही किया है, तो फिर बच्चे पोषित कैसे होंगे. कुपोषण और एक साल तक के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतों की दर उत्तर प्रदेश में है, और यह भी साफ है कि ये मौतें केवल बेहतर खान–पान और सुविधाओं से ही रोकी जा सकती हैं। ■ एजेंसी

संसार की सारी फौजें मिलकर इतना नुकसान नहीं करती जितनी शराब पीने की आदत कर देती है।

सबसे बड़ा त्याग

सुदर्शन भडोला

घुप्प अंधेरा...वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता. हवा का भी नामोनिशान नहीं. ऐसा लगता था जैसे आज ये अंधेरा सबकुछ अपने अंदर लील लेगा. जैसे ये निस्तब्धता का कभी अंत नहीं होगा. कही कुछ भी न तो दिखाई देता था और न ही कुछ सुनाई देता था.

ऐसे में एक वृक्ष उस गहन अंधकार में ऐसे खडा था जैसे एक योगी अपनी किसी कठिन साधना मे तल्लीन हो. उसे आस पास के वातावरण से कोई लेना देना न हो. वृक्ष का ऊंचा कद, उसकी फैली हुई भुजाये उसका सुडौल आकार और पत्तियो का घनत्व उस अंधेरे में उसे भी भयावह बना रहा था, लेकिन एक द्वंद विद्यमान था उसके भीतर. उसकी अपनी पत्तिया, उसकी अपनी छोटी बडी शाखाये, उस पर लगे फल सभी आज एक अकारण से विवाद में उलझे हुए थे. और विवाद था कि जिसका अंत नहीं हो रहा था. सभी अपने को एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण मान रहे थे।

छोटी शाखा का कहना था मेरा महत्व तुम सबसे अधिक है. मैं मनुष्य के जीवन के आरम्भ से ही उसके साथ हूँ. मेरे भीतर की छोटी लकडिया जब उसके चूल्हे में जलती हैं तभी उसका भोजन बनता है. उसका पेट भरता है तभी तो उसका जीवन चलता है. इतना ही नहीं उसके बाल्यकाल में मेरी ही लकडी से ही उसके लिये झूला बनाया जाता है अर्थात चूंकि उसके जीवन के आरम्भिक काल से ही मैं उसके साथ हूँ तो मेरा महत्व सबसे अधिक है। मझोली शाखा ने इतना सुना तो कह उठी क्या मनुष्य की बाल्य अवस्था ही उसका पूरा जीवन है? माना कि तुम उसके भोजन के लिये चूल्हे में जलती हो.. माना कि तुम उसका झूला भी बनती हो..परंतु इसके अतिरिक्त भी मनुष्य को बहुत कुछ चाहिये...उसके जीवन यापन के लिये उसे एक घर भी चाहिये.. . उसके घर के दरवाजे, खिडकियो और शयन के लिये बनी चारपाई में तो मेरा ही प्रयोगहोता है. अगर दरवाजे न हो तो उसकी सुरक्षा कौन करे. अगर उसके शयन का प्रबंध न हो तो फिर वो जीवित कैसे रहे. वो जब बडा होता है तो उसकी क्रीडा के सभी साधन मेरे ही से तो बनते हैं. इसलिये मेरा योगदान तुम सबसे अधिक है। तभी पत्तो ने फुसफुसाना शुरु कर दिया. वो सब मिलकर एक स्वर में कहने लगे. तुम दोनो चुप रहो. हमसे बडा मनुष्य ही नहीं बल्कि किसी भी जीव के जीवन में किसी का महत्व नहीं हो सकता. हमारे ही कारण सम्पूर्ण जीव जगत को श्वास के लिये वायु का निर्माण होता है. हमें खाकर ही मनुष्य के मवेशी और सभी जंगल के प्राणी अपना पेट भरते हैं. हमारी घनी छांव ही पथिक को शीतलता प्रदान करती है और उसके मार्ग को सुगम बनाती है. हमारे ही कारण इस धरा पर जीवन है अन्यथा ये धरा जीवन विहीन हो जाये।

पत्तियो ने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की थी कि फल बोल उठे जाओ मुझसे बढकर कोई भी नहीं है. जब मनुष्य और बाकी जीव मुझे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं तभी तो उनका जीवन चलता है. मेरे ही कारण उनके जीवन चल रहा है. मेरे भीतर के बीज जब फिर से अन्कुरित होते हैं तभी मानवता का जीवन चक्र चल रहा है अन्यथा वह अभी इसी पल समाप्त हो जाये. बिना भोजन कौन कितने दिन तक जीवित रह सकता है और सुनो चूल्हे में जलने वाली लकडी ये बताओ कि अगर मैं नहीं तो फिर भोजन क्या बनेगा? झूले में किसको झुलाओगे.... और हाँ पत्तियो ये तो बताओ क्या प्राणी जगत तुम्हारे द्वारा बनाई हुई हवा खाकर ही जीवित रह सकता है? इसलिये फल का महत्व सबमे अधिक है। तभी उस वृक्ष की एक बडी शाखा बोल उठी तुम सब किस विवाद में पडे हो सबसे अधिक महत्व तुम सबमे मेरा है. देखो मेरे शिखर पर कितने पखेरुओ का ठिकाना है. मैं प्राणी जगत की कितनी सेवा कर रही हूँ. इन पखेरुओ के पूरे परिवार मेरी भुजाओं में अपना आश्रय बनाये हुये हैं. यदि कोई मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो उसकी लाठी भी मेरी ही मजबूत लकडी से बनती है. मैं उसकी वृद्ध अवस्था की साथी भी हूँ. मैं उसके जीवन में तो काम आती ही हूँ इसके अतिरिक्त जब उसकी आत्मा इस संसार से निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसकी निर्जीव देह की सद्गति भी मुझे अग्नि देकर आहुत की जाती है. इसलिये मेरा महत्व तुम सबमे अधिक है. मैं देह में आत्मा होने पर भी उसके काम आती हूँ और आत्मा के देह त्यागने के बाद भी मैं काम आती हूँ. वृक्ष अपने भीतर चल रहे इस घमासान और विवाद को सुनकर अचानक बोल उठा. तुम सब मेरे ही अंग हो. तुम सभी के बिना प्राणी जगत की कल्पना करना भी असम्भव है. मेरे पत्ते अगर छांव देते हैं, मेरे फल अगर किसी की भूख मिटाते हैं और अगर मेरी लकडी जीवन के हर काम में काम आती है तो ये मेरे लिये गर्व की बात है. हमारा जीवन ही इसीलिये है कि हम किसी के जीवन को सवांर सके. हम किसी का घोसला भी हैं तो किसी पथिक के लिये भरी दोपहर में शीतल छांव भी हैं. त्याग ही हम सबका धर्म भी है और हमारे होने का कारण भी. तुम सभी मानव और प्राणी जगत के कल्याण के श्रोत हो. कल्याण के श्रोत कभी भी कम और अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते. कल्याण ही लक्ष्य होना चाहिये और उसके लिये प्रतिस्पर्धा नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की प्रवृति जाग्रत करनी होगी।

आओ हम सब मिलकर प्राणी जगत का कल्याण करे. दम्भ और अभिमान से दिया हुआ दान और किया हुआ कल्याण महत्व को घटाता ही है बढाता नहीं है. वर्षा का जल मेरी जडो में निस्वार्थ भाव से पहुंचकर उनको संचित करता है और वो जडे निस्वार्थ भाव से तुम सबका अर्थात मुझे पोषित करती हैं. यही कल्याणऔर त्याग का मूलमंत्र है. अपने स्वार्थपरक आचरण पर सबने लज्जा से सिर झुका लिये और कल्याण के भाव का आज उनको ज्ञान हो गया था. पूर्व में अब प्रकाश की लालिमा उभर गई थी. पेड पर बैठे पखेरू अब चहकने लगे थे. निस्तबधता का स्थान अब पंछियो के मधुर स्वर ने ले लिया. जीवन के लक्षण अब हर ओर नजर आने लगे. रात का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो गया था. और अज्ञानता का अंधकार भी समाप्त हो गया. योगी वृक्ष मंद मंद मुस्कुरा रहा था उसके हर अंग के नेत्र अब खुल चुके थे।

बिना सोचे समझे किसी को मित्र न बनाएं।

राष्ट्रपति के पास दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने का पूरा आधार

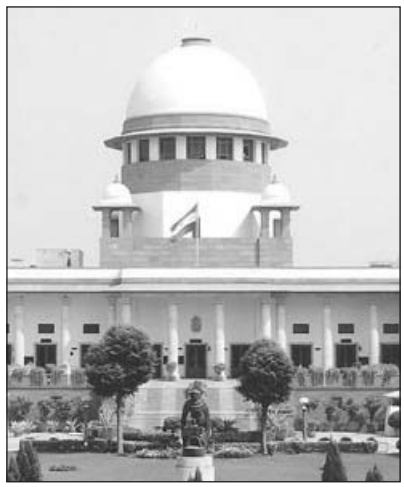

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू अपने बयानों और विचारों को लेकर अकसर खबरों में बने रहते हैं. नए बयान में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के पास अब पूरा आधार है कि वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दें।

जस्टिस काटजू ने दिल्ली की तीनों नगर निगमों के परिणामों के बाद यह बात कही है. जस्टिस काटजू ने कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनावों के बाद मिले परिणामों को देखते हुए राष्ट्रपति को दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रपति के पास उचित आधार है कि वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दें और दिल्ली विधानसभा के चुनाव फिर करवाएं। अपनी बात को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक केस का हवाला भी दिया है. जस्टिस काटजू ने कहा कि स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर1997 एससी 1361 केस में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने यह व्यवस्था दी थी कि अगर कोई पार्टी किसी चुनाव में बुरी तरह हार जाती है तो इसका अर्थ यह है कि अब वह पार्टी लोगों की इच्छा नहीं दर्शाती. और लोग अब पूरी तरह पार्टी के खिलाफ हो गए हैं. यह, यह भी बताात है कि जनता और पार्टी में दूरी आ गई है. जस्टिस काटजू ने कहा, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को राय सबसे अहम है और ऐसा माना जाता है कि विधायक लोगों की राय का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए बाद की किसी भी चुनाव में पार्टी की बुरी हार का मतलब यह है कि पार्टी अब लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती. इसलिए ऐसी सरकार को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है. और पुनरू चुनाव का आदेश दे दिया जाना चाहिए। ■ एजेंसी

लोकपाल की नियुक्ति लटकाकर रखना ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कह दिया है कि वह लोकपाल की नियुक्ति जल्द से जल्द करे, इसे लटकाकर रखना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस संबंध में सफाई देते हुए कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति में देरी इसलिए हो रही है, क्योंकि बिल में कई सारे संशोधन अभी बाकी हैं। उन्होंने दलील दी कि लोकपाल ऐक्ट के मुताबिक सर्च कमिटी में नेता विपक्ष को होना चाहिए, लेकिन अभी इस पद पर कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को कमिटी में शामिल करने के लिए ऐक्ट में संशोधन करना होगा, जो कि यह संसद में लंबित है। इस तरह सरकार ने एक तकनीकी पेच निकालकर मामले को टालने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्पष्ट तौर पर लोकपाल बनाने की बात कही है, तो इसका मतलब यही है कि वह इसे लेकर बेहद गंभीर है।

अदालत ने सरकार को यह इशारा देने की कोशिश की है कि वह अपने स्तर पर तकनीकी बधाएं दूर करें, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति को अब और न टाला जाए। गौरतलब है कि बीजेपी ने पिछले आम चुनाव में इसे एक अहम मुद्दा बनाते हुए जनता से लोकपाल बनाने का वादा किया था। लेकिन सरकार बनाते ही उसने इससे किनारा कर लिया।

नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार और कालेधन को समाप्त करने की बात जोर–शोर से दोहराती रहती है, पर उसके एक भी कदम से ऐसा लगा नहीं कि इसके लिए जरूरी संस्थाओं के सुचारु संचालन को लेकर वह गंभीर है। लो. कपाल के मामले में उसकी दलीलें इस दिशा में जाती हुई लगती हैं कि संसद में किसी एक दल को असाधारण बहुमत मिलना लोकपाल के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ऐसे में कोई विपक्षी पार्टी इस हालत में नहीं होगी कि नेता प्रतिपक्ष का पद उसके हाथ आ सके।

सच कहा जाए तो इसी स्थिति में लोकपाल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सत्ता पक्ष की गड़बड़ियों पर सवाल उठाना ऐसे में संसदीय विपक्ष के बूते से बाहर होता है। देश की विडंबना यह है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाने का काम अभी न्यायपालिका ही कर रही है। कुछ प्रबुद्ध लोगों और सामाजिक संगठनों ने अगर जुडिशरी के स्तर पर लोकपाल का मुद्दा न उठाया होता तो शायद लोग सरकारी नीतियों के प्रचार के शोर–शराबे में इसे भूल ही गए होते।

सरकार की मंशा बार–बार खुद को पाक–साफ बताकर लोकपाल की भरपाई करने की लगती है। आश्चर्य तो यह है कि मीडिया ने भी इस पर बात करना छोड़ दिया है। लोकपाल भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को और पारदर्शी और जिम्मेदार बनाएगा। वही यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोग भी निगरानी से मुक्त नहीं है। केंद्र सरकार को अब लोकपाल के गठन में देर नहीं करनी चाहिए। ■ साभार

भाग्य हमेशा साहसियों का साथ देता है।

जाधव की सजा दोनों देशों के बीच समस्या बन गई है

एक कीड़े ने भारत और पाकिस्तान दोनों, और अब बांग्ला देश को काट रखा है वह है जासूसी। पड़ोसी देश से आने वाला हर व्यक्ति तब तक जासूस समझा जाता है जब तक इसके विपरीत नहीं सिद्ध हो जाता। यह विदेश और गृह मंत्रालयों पर निर्भर करता है कि अमुक व्यक्ति को कब आजाद छोड़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में पुलिस बल ही तय करने वाला होता है। और, यह कहने की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति को मिलने वाली सजा आजीवन कारावास या मौत होगी।

सामान्य तौर पर, अदालत फैसला करती है। लेकिन पाकिस्तान का मामला अलग है क्योंकि वहां सेना शासन करती है। लेकिन नागरिक अदालतों की अपनी भूमिका है जो सेना के स्थानीय कमांडरों पर निर्भर है। वास्तव में अंतिम फैसला उनका होता है। यहां तक कि मौत की सजा भी उन्हीं के द्वारा दी जाती है। सबूत का सवाल पैदा होता है लेकिन यह भी सेना के स्थानीय कमांडरों पर निर्भर करता है।

कराची के अखबार डॉन ने खबर दी है कि जाधव, एक भारतीय व्यापारी को मौत की सजा दी गई है। ''भारतीय रॉ के एजेंट/नेवी अधिकारी 41558 जेड कमांडर कुल भूषण सुधीर जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तान में जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में ब्लूचिस्तान के मस्केल से एक काउंटर इटेलिजेंस आप. रेशन (जवाबी जासूसी कारवाई) के जरिए पकड़ा गया था।''

''जासूस की सुनवाई पाकिस्तान आर्मी एक्ट (पीएए) के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजीएसएम) में की गई और सजा–ए–मौत सुनाई गई,'' आईएसपीआर ने सोमवार को घोषणा की।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने स्वीकार किया है कि जाधव को सजा देने के लिए बहुत कम सबूत थे, लेकिन दूसरी चीजें जाधव का शामिल होना सिद्ध करती हैं। कुछ भी हो सरताज अजीज के शब्द काफी हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव को सारे कागजात जमा किए हैं। उसे विश्वास है कि अगर वह फैसला, अगर कोई देते हैं, तो यह इस्लामाबाद के पक्ष में होगा।

वास्तव में, पड़ोसी देश की यात्रा पर आने वाले के लिए यह नारकीय होता। वह जहां भी जाता है खुफिया विभाग उसका पीछा करता है। यहां तक कि दुकानदार से भी पूछताछ की जाती है मानो उसने भी यात्री को खरीदने की जगह चुनने में मदद की हो। ■ साभार : पीएस

खुले बाजार में नहीं मिल सकेगी सैनिक की वर्दी

भारतीय सेना की यूनिफॉर्म की नकल कर किसी तरह की वारदात को अंजाम देने वालों के लिए अब मुश्किल हो सकती है। सेना ने इस तरह की घटनाओं को देखते हुए ऐसे पैटर्न और सिक्युरिटी फीचर वाली यूनिफॉर्म बनवाने का फैसला किया है, जिनकी कॉपी करना प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए मुश्किल हो। कपड़ों पर आर्मी के पैटर्न और लोगो की नकल न हो सके, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। खास बात यह है कि इस काम में विदेश से कपड़ा मंगाने की जगह देसी इंडस्ट्री की ही मदद ली जाएगी। इसके साथ ही सैनिकों के काम आने वाले कपड़ों और दूसरी असेसरीज को भी आरामदेह बनाने का फैसला किया गया है। इस काम में भारतीय सेना की मदद के लिए राजधानी में देसी इंडस्ट्रीज प्रदर्शनी लगाने जा रही हैं। इसमें आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के साथ कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी रहेगी। करीब 40 भारतीय कंपनियां इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने जा रही हैं। इसमें वे सेना के लिए बनाए गए खास कपड़ों और असेसरीज को दिखाएंगी। प्रदर्शनी के साथ एक सेमिनार भी होगा, जिसका विषय 'सैनिकों के लिए बेहतर उत्पादों का स्वदेशीकरण' है। इस मंच के जरिये पिछले दो साल में इम्पोर्ट का बोझ 20 फीसदी कम किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल बैग और जुराब समेत चार चीजों का स्वदेशीकरण किया गया है। इस बार कुछ और चीजों की पहचान की गई है। 20 और आइटमों की पहचान की गई है, जिन्हें सैनिकों के लिए बेहतर बनाया जाएगा। सेना ने वर्दी और असेसरीज में पूरी तरह स्वदेशीकरण का लक्ष्य तय किया है। कहा जा रहा है कि देसी इंडस्ट्री को शामिल करने से कीमतों में कमी होगी, पारदर्शिता आएगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। ■ साभार

इनका स्वदेशीकरण

1.हल्के और धोए जा सकने वाले दस्ताने, जिन्हें पहनकर फायरिंग तक की जा सके। तीन लेयर में ये माइनस 50 डिग्री तक की ठंड से बचा सकें।

2. बूट, जो 3 किलो से ज्यादा वजनी न हों और इनसोल बदलकर गरमाहट पाई जा सके। ये ग्लेशियर के लिए भी उचित हों।

3. स्लीपिंग बैग माइनस 50 डिग्री की ठंड और 40 किमी प्रति घंटे की हवा से बचा सकें और इनके जिपर पानी में खराब न हों।

4. अत्यंत ठंड के लिए कपड़े, जिनका वजन एक्स्ट्रा लार्ज साइज में साढ़े चार किलो से ज्यादा न हो और माइनस 50 डिग्री में भी राहत दें।

5. चश्मा, जो ऊंचाई वाले इलाकों में रेडिएशन से बचाए।

यदि कोई काम करने लायक है तो उसे दृढ़तापूर्वक करना चाहिए।

रामजन्म भूमि अयोध्या

राम जन्म भूमि का नाम आते ही लोगों के जहन में हिन्दू–मुस्लिम, मंदिर आंदोलन, संघर्ष याद आने लगता है लेकिन कोई राम जन्म भूमि के शहर अयोध्या की परिकल्पना के बारे में नहीं सोचता न ही आंदोलन करता है कि आखिर अयोध्या कैसा हो, मंदिर तो भव्य बनना चाहिए इसकी परिकल्पना एंव चर्चा कई प्रवक्ताओं द्वारा मीडिया में बहुत अच्छी लगती है लेकिन अयोध्या भव्य एवं स्वच्छ साफ सुथरा हो इसके बारे में कोई न तो बात करता है और न कोई कार्यवाही होती है। मंदिर बनने में तो दिक्कत है लेकिन अयोध्या को साफ सुथरा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन आप जहां–जहां जाएं गंदगी अव्यवस्था की भरमार है। अभी हाल में मैं हनुमान गढ़ी गया जहां सीढ़ियों पर भीख मांगने वालों की लाइन लगी रहती है साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है; चारों ओर बंदरों एवं गायों के मलमूत्र फैले हुए हैं, रोड पर अतिक्रमण करके दुकानें खुली हुई हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं राम जी के जमाने की अयोध्या आज भी बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी एंव मुख्यमंत्री योग एवं अन्य हिंदू संगठनों से मेरी अपील है कि अगले स्वच्छता के सर्वे में अयोध्या सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल हो यही रामचंद्र जी एवं राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा काम होगा और स्वर्ग से राम जी अपने शहर को देखकर खुश होंगे और हिंदुओ की आस्था एवं पर्यटन भी बढ़ेगा। साथ में मंदिरों के अवैध कब्जे उनके स्वरुप को बनाए रखने के लिए भी प्रयास करने होंगे नहीं तो यह धार्मिक स्थान अपना स्वरुप खो देगा।

"वानर एवं वैरागीन कीनह अयोध्या नाश"

यह लाइन जब महान कवि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखी होगी तो शायद उन्हें अयोध्या की ऐसी दशा होगी ऐसा बोध न रहा होगा जैसा आज की अयोध्या है। अयोध्या को मुगल काल एवं अंग्रेजी हुकुमत में जितना बर्बाद नहीं किया उससे ज्यादा अब हिन्दू धर्म के ठेकेदार एवं अयोध्या के मंदिर के महन्थों द्वारा किया गया। इसमें सभी को शामिल नहीं किया जा सकता है लेकिन ज्यादातर मंदिर को महंथों द्वारा अपने रिश्तेदारों एवं गृहस्थ को दे दिया जा रहा है और कुछ पर असंवैधानिक तत्वों द्वारा कब्जा करके अन्य कार्यों एवं गृहस्थ के रुप में उपयोग हो रहा है।

यहां मंदिरों का निर्माण कराया गया था जहां भगवान की पूजा अर्चना होती थी साधू संत आ कर ठहरते थे, मेले में तीर्थ यात्री आकर रुकते थे ऐसे स्थानों पर अब लोगा. द्वारा कब्जाकर लिया गया है। ऐसे स्थानों को लोग अब अपने आवास के रुप में प्रयोग करने लगे हैं। भगवान की पूजा अर्चना या मंदिरों को एक कोने में सिमटा दिया गया है। अयोध्या में मंदिरों की जमीन राम लला के नाम से होती है जिसे बेचने पर प्रतिबंध है उसके उपरांत मंदिरों की जमीन धड़ल्ले से बिक रही है। यह दिखाकर कि राम लला को भोग लगाने के लिए पैसे की जरुरत है इसलिए गिरवी रख रहा हूं। इस तरह अयोध्या की धरोहर की बंदरबांट की जा रही है।

बहसबाजी से बचना चाहिए क्योंकि यह ज्यादातर बेकार होती है।

सहारनपुर के दंगे की राजनीतिक चाल

सहारनपुर में जातिगत टकराव के बाद खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय में एक नए तरह की लामबंदी देखी जा रही है। इसे रोहित वेमुला प्रकरण और गुजरात की ऊना दलित चेतना यात्रा के जारी रूप की तरह देखा जा सकता है। दशकों बाद पहली ही बार ऐसा हो रहा है कि यह समुदाय किसी समीकरण से जुड़ी मजबूरियों को पीछे छोड़कर अपने सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में महाराणा प्रताप की शोभायात्रा के दौरान दलितों और ठाकुरों के बीच टकराव ने हिंसक रूप ले लिया था। उकसावे की कार्रवाइयां दोनों तरफ से हुई थीं लेकिन दलितों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रशासन ने समय रहते मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद मामला इस हद तक न पहुंचता। उसकी बेरुखी से दलितों का आक्रोश और भड़का। भीम आर्मी नाम के एक अचर्चित संगठन की अगुआई में बड़ी संख्या में दलितों ने इस घटना के विरोध में दिल्ली के जंतर–मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें देश के अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचे थे। इस विशाल प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से लेकर परंपरागत दलित नेतृत्व तक की नींद उड़ा दी। अपनी सियासी जमीन पर खतरे का अंदाजा लगाकर बीएसपी नेता मायावती भी सहारनपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को छोटे–मोटे संगठनों से बचने की सलाह दी। जाहिर है, उनका इशारा भीम आर्मी की तरफ था। उनका कहना था कि वह शांति कायम करने शब्बीरपुर गई थीं, पर उनके लौटते ही वहां फिर हंगामा हो गया। दरअसल पिछले तीन दशकों से जारी दलित उभार की प्रक्रिया में दलित नौजवानों का एक ऐसा तबका सामने आया है, जो मार खाकर चुप नहीं रहता, और जो सत्ता को ही हर दरवाजे की चाभी बताने वाले कांशीराम के फॉर्मूले की असलियत भी समझ चुका है। वह देख रहा है कि मुख्यधारा की राजनीति में दलित नेता या तो अपना पेट भर रहे हैं, या किसी के पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। दलितों के वोट से बनी सरकारें न तो उनका शोषण रोक पा रही हैं, न ही उन्हें सत्ता में भागीदारी दिला पा रही हैं। ऐसे में ये खुद ही जोखिम उठाकर अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए जो अभियान चलाया था, वह इसी नई चेतना का परिचायक था। ऊना कांड के बाद जिग्नेश मेवानी ने दलितों की यात्रा निकालकर इस मुहिम को गति दी, तो अब उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रातोंरात दलितों के हीरो बन चुके हैं। ■ सं.

पुराना दौर

कुछ देर ही सही वही, पुराना वक्त लौट आये
जिसे हम न जाने कब और कहाँ छोड आये
मा चूल्हे से एक रोटी बना कर उतारे और
हम सब भाई–बहन टुकडे कर बांटकर खाये

न कोई ए.सी. हो न कोई फ्रिज न कोई कार हो
छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा संसार हो
घर के किसी कोने में एक सुराही पडी हो
उसके ठंडे मीठे पानी से अपनी प्यास बुझाये

एक दूसरे का दर्द बांटे एक ऐसा प्यार हो
एक दूसरे की मदद के लिये सब तैयार हो
घर में बनी सब्जी की एक कटोरी दौडकर
अपने पडोस की आंटी को भी थमा आये

दिल बडा हो बेशक किल्लत हो, दिक्कत हो
जूझने का जज्बा हो दुख सहने की हिम्मत हो
कमी में भी बस खुदा की रहमत हो
फर्श पर भी सो जाये जब घर कोई मेहमान आये

न टी.वी. हो, न लैपटाप, न हाथ में फोन हो
हर तरफ चहचहाहट हो न कोई भी मौन हो
रोये, हंसे, लडे–झगडे न कोई भी खामोशी हो
वक्त दे एक दूसरे को, खूब बाते बनाते जाये

अभाव में भी प्रेम रस का हर एक भाव हो
संतोष हो मन में, ज्यादा की न कोई चाह हो
एक सरकारी नौकरी हो पिताजी की
बस एक पिताजी ही कमाये, सब मिलकर खाये

घर के कमरो में कहीन भी मनी प्लांट न हो
सीधे साधे से बचपन में कोई काट छांट न हो
हर घर के आंगन में एक विद्या का पेड हो
हर किताब के बीच में एक मोर का पंख सजाये

एच. एम. टी की घडी सजी हो कलाई में
वही मर्फी का रेडियो बजता हो जोर से
छाया गीत चलाये सिलोन रेडियो पर जोर से
और उतनी ही जोर से साथ में खुद भी गाये

प्रस्तुति : राज राजेश्वर राय

तपती धरती

बुखार से तपती इस धरती को
भला कौन दवा पिलायेगा
तडपती मा को इलाज के लिये
वैद के पास कौन ले जायेगा
पिघल गया है देखो धरती के
माथे पर सजा हिमालय
अब जलते माथे पर बर्फ के
ठंडी पट्टी कौन लगायेगा
हर रोज एक कोना चीर देते हैं हम
धरती के ठंडे से आंचल का
तपते– जलते इसके बदन को कौन
हरियाली की चादर ओढायेगा
इसकी धमनियो में अब खून भी
बहना बंद सा हो गया है
कचरे से भरी दुर्गंध छोडती इन
रुकी नदियो को कौन बहायेगा
हर्म तेल से खौलते हैं इसके चरणो में
झुके सातो महासागर भी
खौलती इस कढाई मे तलती हुयी
ये धरती कौन बचायेगा
सूरज की जलती आंखो से अग्नि का
क्रोध बरबस बरसता है
धधकती हुई इस बेकाबू अग्नि को
कौन आकर बुझायेगा
जिस मा को उसके पुत्र ही उसके
जीते जी चिता पर रख दे
आखिर उस मा को फिर थोडा सा
ढांढस भी कौन बंधायेगा

थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना, और ज्यादा सुनना बस यही बुद्धिमान बनने के उपाय है।

मोदी गये तो श्रीलंका थे पर उनकी निगाहें चीन पर थीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गये तो श्रीलंका थे। पर उनकी निगाहें चीन पर लगी थीं। श्रीलंका जाकर पहला झटका उन्होंने चीन को दिया, जब श्रीलंका ने एक चीनी पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह में ठहरने की अनुमति देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि– यह असंभव है। चीन दशकों से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मोदी के नेतृत्व वाला भारत चीन की हर चाल को काटने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका के साथ टूटते तार को मजबूती से जोड़ने की कोशिश की है।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गये तो श्रीलंका थे, पर उनकी निगाहें चीन की चाल पर लगी थीं। ये महज एक संयोग नहीं था कि उसी दिन चीन के राष्टंपति चीन की उस महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे, जो चीन को यूरोप और मध्यपूर्व के साथ जोड़ने वाली एक अत्यधिक व्यापक बुनियादी ढांचे वाली परियोजना है। रविवार 14 मई को बीजिंग में आयोजित इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से लगभग 30 नेता पहुंचे, लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। चीन की वन बेल्ट एंड वन रोड नामक यह परियोजना प्राचीन रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्र या 21वीं सदी साम. ुद्रिक सिल्क मार्ग के जरिए 100 देशों को जोड़ने वाली एक भीमकाय परियोजना है। पांच महादेशों से गुजरने वाली इस परियोजना पर चीन अब तक 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश कर चुका है। और अनुमान है कि आगे इस पर कुल 900 बिलियन डॉलर का निवेश होगा।

लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से इसलिए इनकार किया, क्योंकि एक तरफ चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भारत के प्रवेश को रोक रखा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर भी उसका रुख नकारात्मक है। इसके अलावा यह परियोजना भारत के पाक कब्जे वाले जम्मू–कश्मीर के उस हिस्से से भी होकर गुजरती है, जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। चीन की इस परियोजना में भारत के शामिल होने से लगता है कि भारत ने पाक कब्जे वाले कश्मीर पर पाक और चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है। लिहाजा भारत ने इसमें नहीं शामिल होने का ठीक फैसला किया। इधर चीन श्रीलंका में भारी निवेश कर वहां भी भारत की राहें मुश्किल बना रहा था। श्रीलंका सार्क में भारत का सबसे बड़ा साझीदार है। लेकिन चीनी निवेश के कारण वहां भी भारत के लिए नयी चुनौतियां खड़ी हो रही थीं। जबकि वहां के कोल. ंबो बंदरगाह में भारत से 70 प्रतिशत से अधिक टांस–शिपमेंट होती है।

■ साभार : पीएस

कोई भी मंत्री सरकारी पॉलिसी के खिलाफ कोई बयान दे सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद को स्वीकार करता है तो वो सामान्य नागरिक के बोलने की आजादी के अधिकार का उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता. ना ही वो सरकारी पोलिसी के खिलाफ कोई बयान दे सकता है।

महिलाओं से रेप और अन्य अपराधों के मामले में ओहदे पर बैठे शख्स द्वारा बयानबाजी का मामला संविधान पीठ को भेजा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में संकेत दिया है।

बुलंदशहर में मां–बेटी के साथ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में महिलाओं से रेप के मामले में ओहदे पर बैठे शख्स द्वारा बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े संवैधानिक सवाल उठाए थे कि देश के संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार, अलग पहचान और गरिमापूर्व जीवन जीने के अधिकार दिए हैं। ऐसे में किसी रेप पीड़ित महिला के खिलाफ ओ. हदे पर बैठे व्यक्ति की बयानबाजी क्या महिला के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को ठेस नहीं पहुंचाती। क्या रेप जैसे गंभीर अपराध को पब्लिक आफिस में बैठा व्यक्ति राजनीतिक साजिश करार दे सकता है?

■ क्या रेप पीड़िता महिला के संविधान के दिए फ्री एंड फेयर ट्रायल का हनन नहीं क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।

■ संविधान द्वारा दिया गया कोई भी मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं क्योंकि ये कानून नियंत्रित है।

■ यहां मामला सिर्फ किसी की बोलने की आजादी का अधिकार का नहीं बल्कि पीडिता के कानून के समक्ष समान संरक्षण और फ्री एंड फेयर ट्रायल के अधिकार का भी है।

■ अगर आरोपी ये कहता है कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया तो बात दूसरी है लेकिन कोई डीजीपी कहता है कि पीड़िता झूठी है तो पुलिस मामले की क्या जांच करेगी?

■ यहां सवाल ये है कि ओहदे पर बैठे व्यक्ति के इस तरह बयानबाजी भले ही कोई अपराध के दायरे में ना हो लेकिन वो संविधान में दिए गए नैतिकता और शिष्टाचार के दायरे में भी आता है।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया. । मुकुल रोहतगी ने कहा इसे लेकर कोई कानून नहीं है. इस तरह कोर्ट मोरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना सकता. हालांकि कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो ट्रायल कोर्ट उस पर अवमानना की कारवाई कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फली नरीमन के साथ साथ हरीश साल्वे को भी कोर्ट से सहयोग करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट बुलंदशहर गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मां–बेटी से गैंगरेप के मामले की जांच कर रही सीबीआई को जल्द जांच पूरी करने को कहा था. वहीं पिछले 15 दिसम्बर को बुलंदशहर गैंगरेप मामले में यूपी के मंत्री आजम खान के पछतावे वाले माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. माफीनामे में रिमोर्स यानि पछतावा शब्द का इस्तेमाल किया गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिना शर्त माफीनामा से भी ऊपर का माफीनामा है।

■ साभार : पीएस

आलस्य वह बीमारी है जिसका मरीज कभी ठीक नहीं होता।

सिकुड़ता जा रहा ऐडवोकेट का पेशा

किसी समय में एडवोकेट प्रोफेशन एक सम्मान एंव रुतबे का पेशा माना जाता था लेकिन धीरे–धीरे इसकी चमक धूमिल पड़ती चली गई और अब सरकार की उदासीनता का शिकार होता जा रहा है जबकि नीति. निर्धारण में एडवोकेट लोग ही बैठे हुए हैं। न्यायालयों में लोक अदालतों के माध्यम से एडवोकेट के पेशे पर काफी प्रभाव पड़ा है। साथ में आयकर बिक्रीकर की वकालत में आने वाले एडवोकेट की प्रैक्टिस कम होती जा रही है उसकी जगह चार्टर्ड एकाउंटेंट ने ले ली है। आर्बिट्रेशन को भी दूसरें लोगों के लिए खोला गया है इसके साथ ही साथ आने वाले जीएसटी में भी बहुत सारा काम एडवोकेट के हाथ से निकल कर सीए के पास जाने वाला है इससे बहुत सारे वकील भाइयों के जीवीकोपार्जन की भी समस्या होने वाली है।

इसके अलावा एनसीएलटी इत्यादि में एडवोकेट की भूमिका सरकार द्वारा कम की जा रही है, लेकिन एडवोकेट के हितों के लिए बनाई गई संस्थाएं कुछ नहीं कर रही हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली नोकिया फोन की तरह से आउट डेटेड होती जा रही है जब कि आज का समय एंड्रायड का है बाकी इंस्टीट्यूट जैसे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए इत्यादि मासिक पत्रिका निकालते हैं अपने सदस्यों को अपडेट करते हैं अपनी गति. विधियों को लोगों तक पहुंचाते हैं लेकिन बार काउंसिल द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है। हां चुनाव जितने के लिए करोड़ों रुपए जरुर खर्च कर दिया जाता है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बार काउंसिल है। केंद्र सरकार इसका प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है और उच्चतम न्यायालय होने के कारण भी इसका महत्व बढ़ जाता है। एडवोकेट पेशे की गरिमा बनाए रखने एंव इसके कार्य क्षेत्र में दूसरे का प्रवेश नहीं देना चाहिए। कानून की व्याख्या का काम एडवोकेट का है उसमें दूसरें पेशे के लोगों को सरकार द्वारा अनुमति देना संविधान सम्मत नहीं है।

दिल्ली जैसे शहर में कम्पनी के छोटे से छोटे कर्मचारी को ठीक से बैठने की व्यवस्था इतनी गर्मी में एसी की व्यवस्था दी जाती है जबकि दिल्ली कोर्ट में वकीलों को जो सीट दी गई वहां न तो एसी की व्यवस्था है न कोई आवश्यक सुविधाएं हैं।

कड़कड़डूमा कोर्ट की सफाई व्यवस्था ठीक करने की जरुरत है। अभी नई कमेटी गठित हो गई है उससे अनुरोध है कि सभी ब्लाकों में शौचालयों की उचित सफाई कराई जाए यदि हो सके तो साकेत कोर्ट मॉडल के रुप में अपनाया जाए या वहां की सफाई एजेंसी को यहां की भी सफाई व्यवस्था दी जाए।

जीएसटी का खौफ

जीएसटी के 1 जुलाई से देशभर में लागू करने को लेकर चल रही तमाम कवायदों के बीच वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आने वाले सीबीईसी ने हाल ही में जीएसटी की रेट लिस्ट जारी की और आम आदमी को बताया कि उसके प्रतिदिन के काम काज और जरूरतों से जुड़ी किन चीजों को NIL स्लैब में रखा गया है और किन पर कितना फीसदी टैक्स लगाया गया है. सरकार ने कहा है जीएसटी लागू होने के बाद खाद्यान्न, आटा, दूध, सब्जियां और फल सस्ते हो जाएंगे. साथ ही सरकार के मुताबिक, दूध, सब्जियां, फल, पके चावल, नमक, जैविक खाद, पशु चारे, जलावन, कच्चे रेशम, उन, हाथ से चालित औजार भी नयी परोक्ष कर व्यवस्था में शून्य दर लगेगी।

जीएसटी के तहत 5 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान– चीनी, चाय, भुने हुई कॉफी बीन्स, खाने योग्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए मिल्ड फूड, पैक्ड पनीर, सूती धागा, फैब्रिक, सरकंडे की झाड़ू 500 रुपये तक की फुटवेयर, न्यूजप्रिंट, पीडीएस के तहत मिलने वाला केरोसिन, घरेलू एलपीजी, कोयला, सोलर फोटोफोलटैक सेल और मॉड्यूल, कॉटन फाइबर, कपड़े जोकि 1000 रुपये तक के हों।

जीएसटी के तहत 12 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान– मक्खन, घी, मोबाइल, काजू, बादाम, सॉस, फलों का जूस, नारियल पानी, अगरबत्ती, छाता, कपड़े जोकि 1000 रुपये से अधिक हो।

जीएसटी के तहत 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान– हेयल ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल इंटरमीडियरीज, पास्ता, कॉर्न फ्लैक्स, जैम, सूप, आइसक्रीम, टॉयलेटध्फेशियल टिश्यूज, आयरनध्स्टील, फाउंटेन पेन, कंप्यूटर, मानवनिर्मित फाइबर, 500 रुपये से अधिक के फुटवेयर. जीएसटी के तहत 28 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान– उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट, चुइंग गम, कस्टर्ड पाउडर, परफ्यूम, शैंपू, मेकअप, पटाखे और मोटरसाइकल।

यहां बताते चलें कि सरकार का कहना है कि 81 फीसदी चीजें ऐसी हैं जो 18 फीसदी से कम के जीएसटी स्लैब में आती हैं. केवल 19 फीसदी सामान ही इससे ऊपर के दायरे में आता है। **एजेंसी**

बिना प्रयास के आपके पास सिर्फ एक ही चीज आती है और वह है आपका बुढ़ापा।

दवा का दर्द

अस्पतालों में खुलेआम लूट हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री राहत कोष तक का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार से सस्ती दर पर जमीन ली जाती है कि गरीबा. का फ्री इलाज होगा लेकिन उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। टेस्टके नाम पर फिफ्टी–फिफ्टी का धंध चल रहा है जो टेस्ट पंजाब में 150 रुपए के होते हैं दिल्ली में 1000 के हो रहे हैं।

नए–नए सपनों में सस्ते इलाज का एक और सपना जुड़ गया है. देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सबको पता है. महंगे इलाज की सुविधाएं जिस तरह बढ़ रही हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबको स्वास्थ्य का हमारा इरादा किस तरह हारता चला जा रहा है. सरकार को कुछ करते दिखना जरूरी होता है, सो, कई दशकों से हमेशा नए–नए सरकारी कार्यक्रम या मिशन सुनने में आते रहे, लेकिन हालात में खास फर्क नजर नहीं आया, बल्कि बढ़ती आबादी के अनुपात में अस्पतालों में भीड़ जरूर बढ़ती जा रही है. यह हकीकत कोई एक–दो जगह की नहीं, और कोई ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं बचा, जहां डॉक्टरों और दवाओं की कमी न हो, इसीलिए इस मामले में निजी क्षेत्र दिन–दूनी रात–चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है. बहरहाल भारत सरकार ने इस समय दवाइयों के दाम कम कराने का नारा छेड़ा है, सो आइए, जरा इसका आगा–पीछा देखें...

बीमारी का समाजशास्त्र... : मानव जीवन की अब तक की ज्ञात विपदाओं में सबसे ज्यादा सार्वभौमिक और सर्वकालिक विपदा शारीरिक रोगों को ही माना जाता है. आधुनिक समाजशास्त्री बीमारी को सामाजिक विघटन का रूप और कारण दोनों मानते हैं. इस तरह रोग या बीमारी को सिर्फ व्यक्तिगत विघटन या पारिवारिक विघटन ही नहीं माना जाता, और इसीलिए कोई भी सरकार, खासतौर पर लोकतांत्रिक सरकार, स्वास्थ्य सेवा को अपनी प्राथमिकताओं में रखती है. अब यह अलग बात है कि अपनी प्राथमिकताओं को दिखाने के लिए आमतौर पर सरकारें नीतियां बनाने का प्रचार ही कर पाती हैं, उन्हें लागू कर सबको स्वास्थ्य मुहैया कराने का मकसद पूरा करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है.

बीमारी का राजनीतिशास्त्र...: हर काम को आगे के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन बीमारी ही है, जिसे तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है. इसमें कोई शक नहीं कि देश की आजादी के समय मृत्युदर का जो आंकड़ा था, वह सुखद आश्चर्य की तरह घटा है. पिछले सात दशक में हमने देश में कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और साफ–सफाई के काम को राजनीतिक तौर पर कितनी तवज्जो दी, यानी यह सेवा कितनी कम–ज्यादा थी, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आजादी के समय हमारी माली हालत जैसी थी, उसमें हमने अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत ढांचा खड़ा करने में कोई कम दम नहीं लगाया. आज का रोना यह नहीं है कि अस्पताल नहीं हैं, बल्कि हर तरफ से ख़बर आती है कि अस्पतालों में डॉक्टर कम हैं और दवाइयां हैं ही नहीं.

राजनीतिक तौर पर आज स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत ढांचे का काम काफी कुछ निपटा हुआ नजर आ रहा है. आज इन सुविधाओं के समान वितरण की नई चुनौती है. मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने से पहले जिस तरह श्सबका साथ सबका विकासश नारे का सहारा लिया था, वह सबूत है कि सरकार मानती है कि अब सबको समान सुविधाएं देने का काम शुरू होना है. स्वास्थ्य सेवा तक गरीब की पहुंच हो जाए, इसके लिए जो कुछ भी हो, उस पर ज्यादा टीका–टिप्पणी का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन गरीबों को सस्ती दवाएं दिलवाने के लिए कानून बनाने और उसे लागू करवाने की प्रणाली पर जरूर सोचना पड़ेगा. खासतौर पर तब, जब देश की आबादी हर साल दो करोड़ की रफ्तार से बढ़ रही हो और न्यूनतम स्तर का जीवनयापन करने वालों की संख्या, यानी गरीबों की भी उसी अनुपात में बढ़ रही हो।

दवाओं का अर्थशास्त्र... :इस मामले में नई बात यह उठी है कि एक ही दवा के दामों में भारी अंतर है. एक दवा वह है, जो उसमें मौजूद रासायनिक यौगिक के नाम से जानी जाती है. उन्हें जेनेरिक दवाएं कहा जाता है. दवाओं के दूसरे वर्ग का नाम ब्रांडेड दवाएं हैं. यानी, एक ही दवा को अलग–अलग प्रकार से या ज्यादा बारीकी से असरदार दिखाने के लिए अलग–अलग फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने ब्रांड नाम से बेचती हैं. ब्रांडेड दवाओं के दाम औसतन तीन से पांच गुना तक हैं. इन्हीं ब्रांडेड दवाओं के खिलाफ माहौल बनाने का प्रचार हो रहा है. सरकारी तौर पर कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर लोग सस्ती दवाएं, यानी जेनेरिक दवा ही पर्चे में लिखा करें. डॉक्टरों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे दवा बनाने और बेचने वालों से मेल–मिलाप बढ़ाकर गरीब बीमारों को भी महंगी दवाएं लिखते हैं।

क्या इतनी आसान है ब्रांडेड दवाओं की मुखालफत...?

जेनेरिक दवा में जो पदार्थ है, उसका दाम, उसे गोली–कैप्सूल के आकार में लाकर उसका पत्ता बनाने का दाम फिर भी तय हो सकता है. उस नाम से कोई भी कंपनी दवा बनाए, तो उसे बाजार की गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा से निपटना होता है. लेकिन उसी दवा को नए–नए शोधों के जरिये ज्यादा कारगर तरीके से खून में जल्द या देर से मिलाने की प्रणाली विकसित करने के नाम पर कंपनियां अपने–अपने ब्रांड बनाकर ताबड़तोड़ प्रचार करती हैं. जनता के बीच दवाइयों के प्रचार पर पाबंदी है, लेकिन डॉक्टरों के बीच प्रचार पर रोक नहीं है. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जरिये दवा कंपनियां जो भारीभरकम खर्च करती हैं, वह खर्च जेनेरिक दवाओं को बेचने के लिए नहीं, बल्कि महंगी ब्रांडेड दवाएं बेचने के लिए ही होता है. अभी मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों के बीच तालमेल बनाकर किसी ब्रांडेड दवा को ज्यादा बिकवाने का अंदेशा बना हुआ है. हमारी सरकार इसी अंदेशे को खत्म करने के लिए कोई कानूनी उपाय करने की बात कह रही है. ऐसे फायदे की बात सुनकर जनता का खुश होना स्वाभाविक है. अब सवाल यह है कि दवाओं को सस्ता करवाने का यह काम होगा कैसे...?

एक समर्थ व्यक्ति के पीछे हमेशा कई समर्थ सहयोगी होते है।

चुटकुले

■ **एक अभिनेत्री (अपने लेखक पति से)** – याद रखो , अगर आज फिर शराब पीकर घर आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी

पति – प्रिय ! तुम रोज सुबह यही बात कहती हो परन्तु न तो तुम अपना वादा पूरा करती हो और न मैं शराब पीना ही छोडता हूं।

■ **अपने वकील पति से पत्नी ने कहा –** ए जी , फ्रिज और टी.वी कब लीजिएगा ? पडोसन के यहां दोनों चीजें हैं द्य

वकील पति – ने मुस्कराकर जवाब दिया – कुछ दिन और सब्र करो द्य एक तलाक का मुक. दमा हाथ में हैं।

जैसे ही उनका घर उजडेगा , अपना घर बस जाएगा।

■ **पत्नी :** इतने साल हो गये शादी को तुमने आज तक मुझे कुछ नही दिया
पति : दिल तो दिया है और क्या चाहिये
पत्नी : नहीं जानू कोई सोने की चीज दिलाओ ना
पति : चलो शाम को नया तकिया ला दूंगा फिर खूब मजे से सोना।

■ **पत्नी :** अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे?
पति : मैं अखबार में इश्तेहार दूंगा।
पत्नी : तुम कितने अच्छे हो। क्या लिखोगे?
पति : जहां भी रहो खुश रहो।

■ कब्रिस्तान के आगे दो व्यक्ति बात कर रहे थे :
"कितने आराम से सो रहे हे ये लोग"
उतने में एक मुर्दा खडा हो गया और बोला ,
क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है!

■ **साधू :** बच्चा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ।
लड़का : ठीक है दक्षिणा में आपको मैंने दिल्ली दी। आज से दिल्ली आपकी हुई।
साधू : दिल्ली क्या तुम्हारी है ? जो मुझे दे रहे हो।
लड़का : तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है, जो तू उधर के प्लाट यहाँ बांट रहा है।

■ मुझे भी आज हिंदी बोलने का शौक हुआ,

घर से निकला और एक ऑटो वाले से पूछा,

"त्री चक्रीय चालक पूरे सुभाष नगर के परिभ्रमण में

कितनी मुद्रायें व्यय होंगी ?"

ऑटो वाले ने कहा, "अबे हिंदी में बोल रे.."

मैंने कहा, "श्रीमान मै हिंदी में ही वार्तालाप कर रहा हूँ।"

ऑटो वाले ने कहा, "मोदी जी पागल करके ही मानेंगे ।

चलो बैठो कहाँ चलोगे ?" मैंने कहा, "परिसदन चलो"

ऑटो वाला फिर चकराया ! "अब ये परिसदन क्या है ? बगल वाले श्रीमान ने कहा, "अरे सर्किट हाउस जाएगा"

ऑटो वाले ने सर खुजाया बोला, "बैठिये प्रभु"

रास्ते में मैंने पूछा, "इस नगर में कितने छवि गृह हैं ??"

ऑटो वाले ने कहा, "छवि गृह मतलब ??"

मैंने कहा, "चलचित्र मंदिर" उसने कहा, "यहाँ बहुत मंदिर हैं

राम मंदिर, हनुमान मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर"

मैंने कहा, "भाई में तो चलचित्र मंदिर की

बात कर रहा हूँ जिसमें नायक तथा नायिका प्रेमालाप करते हैं ३"

ऑटो वाला फिर चकराया, "ये चलचित्र मंदिर क्या होता है ??"

यही सोचते सोचते उसने सामने वाली गाडी में टक्कर मार दी ऑटो का अगला चक्का टेढ़ा हो गया और हवा निकल गई।

मैंने कहा, "त्री चक्रीय चालक तुम्हारा अग्र चक्र तो वक्र हो गया ३"

ऑटो वाले ने मुझे घूर कर देखा और कहा, "उतर जल्दी उतर !

आगे पंचर की दुकान थी हम ने दुकान वाले से कहा३.हे त्रिचक्र वाहिनी सुधारक महोदय

कृप्या अपने वायु ठूंसक यंत्र से मेरे त्रिचक्र वाहिनी के द्वितीय चक्र में वायु ठूंस दीजिये धन्यबाद

दूकानदार बोला कमीने सुबह से बोनी नहीं हुई और तू शलोक सुना रहा है।

सफलता के तीन रहस्य हैं– योग्यता, साहस, और आपकी कोशिश

''वीआईपी कल्चर''

1 मई से देश में लालबत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मोदी सरकार के फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री की मानें तो उन्होंने इस फैसले से देश में आम और खास का फर्क मिटा दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ लालबत्ती हटाने से देश में वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा?

चलिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जनता की नजरों में ऊंचा दिखने के लिए हमारे नेता इसका त्याग कर देंगे...लेकिन क्या सड़क पर उनका काफिला भी निकलना बंद हो जाएगा? क्या देश के टोल नाकों पर नेताओं का समर्थकों के साथ हंगामे पर भी ब्रेक लगेगा? क्या लालबत्ती हटने के बाद हमारे नेता आम आदमी की तरह बिना सुरक्षा के सड़कों पर निकलेंगे?

सवाल कई हैं...सिर्फ लालबत्ती से तौबा कर लेने से आम और खास में फर्क नहीं मिटेगा। दुनिया के ज्यादातर देशों में वीआईपी कल्चर नहीं के बराबर है। उदाहरण के तौर पर स्वीडन और नार्वे को लीजिए... वहां के प्रधानमंत्री आम नागरिक की तरह ट्रेनों में सफर करते हैं। उनके साथ कोई काफिला नहीं होता, और तो और नार्वे के राजा अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं।

क्या हमारे नेता खुद गाड़ी चलाकर संसद जाएंगे? क्या हमारे मंत्री सरकारी वाहन त्याग कर रोजाना मेट्रो में सफर करेंगे? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को आप सभी ने लंदन में मेट्रो में सवारी करते देखा होगा...कैमरन ट्यूब की सवारी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें सुर्खियों में आना था....ना ही उन्हें फोटो खिंचवाने का शौक था...कैमरन ट्रेन में इसलिए सफर करते थे ताकि ट्रैफिक में उनका समय बर्बाद ना हो और ना ही उनके कारण लंदन की जनता को किसी तरह की तकलीफ हो।

जिस देश में सरकारी विमान में पसंदीदा सीट नहीं मिलने पर एक सांसद कर्मचारी की सरेआम चप्पल से पिटाई कर दे वहां वीआईपी कल्चर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा ये कहीं से हजम नहीं होता। जब एयर इंडिया ने इस बर्ताव के लिए सांसद रवींद्र गायकवाड़ को ब्लैकलिस्ट किया तो शिवसेना ने पूरा संसद सिर पर उठा लिया। हमारे देश में सत्ता के नशे में नेता क्या–क्या कर जाते हैं ये हर किसी को मालूम है...कहीं कोई टोल प्लाजा कर्मचारी की पिटाई कर देता है ...तो कहीं कोई नेता किसी जिले में डीएम को सरेआम गाली देकर जलील करता है। हमारे देश के नेता सत्ता की हनक में ये भूल जाते हैं कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में किस तरह बर्ताव करना चाहिए। जनता के पैसे पर मौज करने वाले नेताओं की लालबत्ती लगी गाड़ी में तो घूमना बंद हो जाएगा...लेकिन जब तक उनकी बाकी सुविधाएं खत्म नहीं कर दी जातीं तब तक उन्हें आम बताना बेमानी होगी। क्या मोदी सरकार संसद में बिल लाकर सांसदों की मुफ्त हवाई सेवा, ट्रेन सेवा और दूसरी सुविधाएं खत्म कर सकती है....रेलवे की वीआईपी लिस्ट में शामिल सांसदों का यात्रा के दौरान ट्रेन में किस तरह आवभगत होता है ये हर किसी को मालूम है। जिस देश की राजधानी दिल्ली में वन रूम फ्लैट खरीदने में लोगों का पूरा जीवन गुजर जाता है...वहां हमारे नेता आलीशान बंगले में ठाठ फरमाते हैं। मुफ्त घर, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त चिकित्सा...जनाब आप नाम लेते जाइए इनकी सुविधाओं की लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। अपने देश में किसी वीआईपी की सुरक्षा के लिए आमतौर पर 17 जवानों को लगाया जाता है...जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सिर्फ लालबत्ती हटाकर नेताओं को खास से आम नहीं बनाया जा सकता.... परिपक्व लोकतंत्र में राजनेताओं का बर्ताव आम इंसान की तरह होना चाहिए...क्योंकि उसे सत्ता की बागडोर किसी और ने नहीं जनता ने सौंपी है। हमारे देश से वीआईपी कल्चर तभी खत्म होगा जब हमारे नेता आम इंसान की तरह सोचना शुरु करेंगे।

तूफान जितना बड़ा होगा वह उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा।

विकास की आधुनिक लूट

आलोक सोलंकी

जनता को बिल्डरों, विकास प्राधिकरण केलोगों एवं नेताओं ने बुरी तरह से लूट लिया है। लगभग तीन लाख करोड़ से ऊपर की धनराशि की लूट छोटे से लेकर बड़े बिल्डरों ने लूटी है। जनता एवं बैंक को लुटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी तंत्र की भी रही है।

इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार लोगों को मकान बनाकर दे ही नहीं सकती क्योंकि इतना जबर्दस्त भ्रष्टाचार है कि सरकार द्वारा बनाई गई 10 मंजिला बिल्डिंग बनते–बनते ढह जाएगी और लागत इतनी आ जाएगी कि इतने में तीन बिल्डिंगे बन जाए। सभी जगह सरकार द्वारा मकान की योजना फेल है देश की राजधानी दिल्ली में डीडीए द्वारा बनाए गए मकानों एवं उनमें भ्रष्टाचार की कहानी बताने की जरुरत नहीं है।

अब जब सरकार फेल हो जाती है या नीति निर्देशकों द्वारा फेल करके अपने हितों को साधने के लिए प्राइवेट हाथों में धंधा चालू कर दिया जाता है और यहां से जनता को लूटने का काम चालू हो जाता है। इसी तरह कुछ समय पहले दिल्ली में सीलिंग का खेल खेला गया था, जो लगभग सभी बुद्धिजीवियों को इसकी हकीकत के बारे में पता है।

अंग्रेजों एवं मुगलों से ज्यादा लूट

अब हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की जिसमें नोएडा एवं गाजियाबाद आता है। राजनेताओं अफसरों की मिलीभगत से विकास प्राधिकरण ने जनता को पूरी तरह से लुटवाने का काम किया और इसमें बैंकों का भी करोड़ों का पैसा भी डूबा जो मकान नहीं लिए थे लेकिन बैंकों में निवेश किए थे। विकास प्राधिकरण ने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ तथाकथित आकाओं के शह पर औने–पौने बिना दामों में जमीनें बिल्डरों को दे दी, और इन्हीं जमीना. पर सपना दिखाकर लोगों के जीवन भर की कमाई ले ली। साथ में बची हुई जिंदगी को कर्ज में डाल कर मौज लेने लगे। जिस नेता को बिजनेस की एबीसीडी नहीं आती वह बड़े व्यापारी इस नंबर दो के पैसे से बन गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्ष के शासन में रहे नेताआ., ऑफिसरों, बिल्डरों की सारी सम्पत्ति यदि जोड़ दी जाए तो पूरी सम्पत्ति से ज्यादा इनके पास होगी। जेपी जैसी कम्पनी लगभग एक लाख लोगों का औसतन पचास लाख रुपया लेकर बैठी है और पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं हो रही है। अब तो बिल्डर जेलों में भी जुगाड़ लगाकर मौज करने लगे हैं।

कुछ बिल्डरों ने तो अपने बचाव में पहले से ही उसी तरह से व्यवस्था कर रखी है जैसे कम्प्यूटर में वायरस के लिए हम पहले ही एंटी वायरस डाल देते हैं। इस गोरखधंधे में सिर्फ बिल्डर दोषी हैं ऐसा नहीं है, जब सत्ता में बैठे लोग इसमें शामिल होते हैं तो इन्हें भी करना पड़ता है। लोगा. को रहने के लिए मकान चाहिए, मकान लोगों का सपना होता है जिस जगह सरकारें नाकाम होती हैं वहां जनता की लूट होती है यही हाल शिक्षा, चिकित्सा, इत्यादि में देखा जा रहा है। अभी तक भ्रष्टाचार राज्य की नीति हो गई थी अब माननीय योगी जी से लोगों को उम्मीद जगी है लेकिन जख्म इतना बड़ा है कि भरने में समय लगेगा सभी बिगड़ चुके हैं।

असफल व्यक्तियों में से 99 फीसदी वे लोग होते हैं जिनकी आदत बहाने बनाने की होती है।

भारतीय न्यायालय ने कहा कि मेरी कोई सुनता नहीं

यह हमारे स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक है किंतु उच्चतम न्यायालय का कहना सही है कि उसकी कोई सुनता ही नहीं। कई महत्वपूर्ण निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं जिस पर न तो राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार और न ही अधीनस्थ न्यायालय ही कोई अमल करते हैं।

अवैध निर्माण, पर्यावरण पुलिस व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले, महिला सुरक्षा इत्यादि पर कई महत्वपूर्ण निर्णय एंव दिशा निर्देश के बावजूद शासन प्रशासन द्वारा न तो कोई कार्यवाही होती है और न उस पर कोई अमल किया जाता है। न्यायालय में भी उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों को सही से लागू नहीं कराया जाता है।

सजा एवं फैसला, कानून एवं अपराध के आधार पर न होकर वकील की फीस एवं पहुंच के आधार पर हो रहा है।इस कारण मेहनती का कानून के जानकार वकीलों के मुकाबले जुगाड़ एवं भाई, भतीजे वाले वकील चांदी काट रहे हैं, वहीं न्यायालयों में 90 फीसद वकीलों को आर्थिक तंगी, न्यायाधीशों अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालयों में वकीलों के साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। सही होने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता है। मुवक्किल के निदोष होने के बावजूद जमानत नहीं मिलती वहीं कुछ वकील निश्चित जमानत कराने का ठेका लेकर जमानत कराते हैं और ऐसे वकील दस फीसद ही होते है।

शासनादेश का उल्लंघन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया है कि बिल्डर द्वारा बनाए गए फ्लैटों में कुछ फ्लैट गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए बनाना होगा और उसे उन्हें कम कीमत पर देना होगा लेकिन कोई भी बिल्डर इस सरक. ारी आदेश को नहीं मान रहा है जिस कारण वैशाली इंदि. रापुरम, कौशाम्बी में झुग्गी बस्ती बढ़ती जा रही है और गरीब लोग जानवरों से बुरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की आने वाली नई सरकार इस खबर को संज्ञान में लेकर जनहित में उचित कार्यवाई करे।

सराहनीय प्रयास

नोएडा टोल को समाप्त करवाने में जिन लोगों का प्रयास रह है वह सराहना एवं सम्मान के योग्य है। क्योंकि न तो किसी राजनीतिक पार्टी के और न तो कोई नेता न ही प्रशासन इसे खत्म करने के लिए तैयार था जबकि सबको पता था कि यह अवैध वसूली उसी तरह है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लोग न्यायालय में गए और आंदोलन भी किया अंततः टोल समाप्त हो गया। अब सरकार को व हमारे नीति निदेशकों को यह समझ लेना चाहिए कि टोल के नुकसान क्या है।

1. प्रदूषण फैलता है।
2. तेल की बर्बादी होती है।
3. समय का नुकसान होता है।
4. आपातकालीन सुविधाएं प्रभावित होती है जैसे मरीज के समय से अस्पताल न पहुंचना।
5. भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

हमारी संस्था लोक जागृति देश में सभी जगह टोल समाप्त करने की मांग करती है। इससेजो भी रेवेन्यू का नुकसान होगा उसे गाड़ी खरीदते समय एक साथ रोड टैक्स को बढ़ाकर एक किया जा सकता है। सरकार को जितना टोल टैक्स से आय होती है उससे अधिक उसके रखरखाव टोल बूथ बनाने में खर्च हो जाता है।

मनीष मिश्र एएसपी के पद पर प्रोन्नत

सीओ सेकंड मनीष मिश्र को अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रोन्नति मिली है। शासन की तरफ से बुधवार देर रात 22 अधिकारियों की सूची जारी की गई थी। 2001 बैच के पीपीएस अधिकारी मनीष मिश्र मूल रूप से गोंडा के रहने वाले हैं। गाजियाबाद में मार्च–2016 से क्षेत्राधिकारी द्वितीय पद पर कार्यरत हैं। इसी साल उन्हें सर्वोच्च पुलिस पदक गैलेंट्री अवॉर्ड से भी नवाजा गया है। वह लखनऊ एसटीएफ में भी रह चुके हैं।

किसी राज्य को चलाने में अच्छे कानून के साथ अच्छे अधिकारी भी जरुरी हैं।

तापमान बढ़ने से परेशान धरती

नीरज बंसल

पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यह सर्वविदित और निर्विवाद तथ्य है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी अन्तर–सरकारी समिति के साथ कार्यरत 600 से ज्यादा वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कारणों में सबसे अधिक योगदान मनुष्य की करतूतों का है। पिछली आधी सदी के दौरान कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के फूँकने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा खतरनाक हदों तक पहुँच गई है। मोटे अनुमान के मुताबिक आज हमारी आबोहवा में औद्योगिक युग के पहले की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है।

सामान्य स्थितियों में सूर्य की किरणों से आने वाली ऊष्मा का एक हिस्सा हमारे वातावरण को जीवना. `पयोगी गर्मी प्रदान करता है और शेष विकिरण धरती की सतह से टकराकर वापस अन्तरिक्ष में लौट जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वातावरण में मौजूद ग्रीनहाउस गैसें लौटने वाली अतिरिक्त ऊष्मा को सोख लेती हैं जिससे धरती की सतह का तापमान बढ़ जाता है। ऐसी आशंका है कि 21वीं सदी के बीतते–बीतते पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

भारत में बंगाल की खाड़ी के आसपास यह वृद्धि 2 डिग्री तक होगी जबकि हिमालयी क्षेत्रों में पारा 4 डिग्री तक चढ़ जाएगा। अंकों में यह वृद्धि भले मामूली लगे लेकिन इसका असर समूची मानव सभ्यता में भारी उलटफेर करने की क्षमता रखती है। आज मौसम के अप्रत्याशित व्यवहार को धरती के तापमान बढ़ने से जोड़ा जा रहा है। सूखा, अतिवृष्टि, चक्रवात और समुद्री हलचलों को वैज्ञानिक तापमान वृद्धि का नतीजा बताते हैं। पिछले छह दशकों में ध्रुवीय बर्फ भण्डारों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है।

नासा के एक अध्ययन के अनुसार मौजूदा सदी के बीतते–बीतते इस कमी से समुद्री जलस्तर वृद्धि के परिणामस्वरूप दुनिया भर की तटीय बस्तियाँ जलमग्न हो चुकी होंगी। दूसरी ओर खेतिहर मैदानी इलाकों में पानी की किल्लत कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर डालेगी। धरती का तापमान बढ़ने से समूची जलवायु बदल जाएगी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खासतौर पर जीव–जन्तुओं और पौधों पर दिखाई देने लगा है। मेढक से लेकर फूलदार पौधों तक में प्रकट हो रहे बदलाव असम्बद्ध घटनाएँ नहीं हैं बल्कि धरती के गरम होने

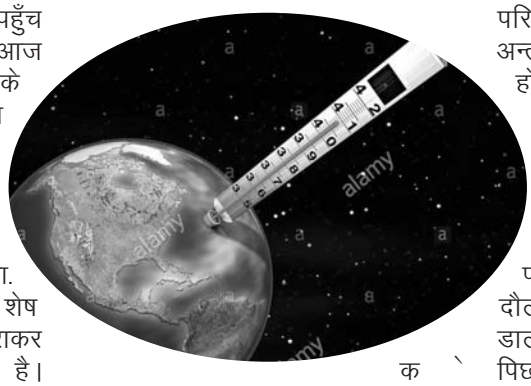

क ` संकेत चिन्ह हैं। पौधों व जन्तुओं की 1700 प्रजातियों पर हुए एक अध्ययन के अनुसार ये प्रजातियाँ लगभग 6.1 किलोमीटर प्रति दशक की गति से ध्रुवों की ओर खिसक रही है और प्रत्येक दशक के बाद वसंत के मौसम में जन्तुओं के अंडे देने व प्रसव काल में 2. 3 दिनों की कमी दर्ज की गई है। ढाई हजार किलोमीटर में फैले हिमालय पर्वतमाला में जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के अनेक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं और वृक्ष घटते जा रहे हैं। गंगा का पवित्र उद्गम गोमुख ग्लेशियर पिछली एक सदी में 19 किलोमीटर से अधिक सिकुड़ गया है और आज इसके सिकुड़ने की रफ्तार 98 फीट प्रतिवर्ष है। ग्लेशियरों के पिघलने की यह गति बनी रही तो सन 2035 तक मध्य व पूर्व हिमालय के सारे ग्लेशियर लुप्त हो जाएँगे। कुदरत के साथ छेड़खानी का खामियाजा बेजुबान जानवरों के साथ साथ हाशिए पर रहने वाले लोग उठाते हैं। जंगलों, नदियों, समुद्र तटों व प्राकृतिक संसाधनों पर सदियों से आश्रित आदिवासी व कमजोर तबकों का अस्तित्व एवं आजीविका औद्योगिक विकास और शहरीकरण की भेंट चढती रही है। बाँधों–खदानों से उजडने वाले बेसहारा महानगरों की ओर ऐसे ही नहीं उमड़ते। शहरों में कोढ़ की तरह दुत्कारे जाने वाले इन 'पारिस्थितिकीय शरणार्थियों' को प्रकृति के साथ आदमी की छेड़छाड़ के दुष्परिणामों का पहला शिकार माना जाना चाहिए। लेकिन इनकी दुर्दशा और विस्थापन ने कभी ऐसा शोर नहीं पैदा किया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अन्तरसरकारी समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद थोड़ी हलचल हुई, फिर लगता है कि सब कुछ सामान्य गति से चलने लगा है। हालांकि 113 देशों के 620 शीर्ष वैज्ञानिकों की पाँच साल की माथापच्ची से निकली रिपोर्ट ने दुनिया के सारे संसाधनों पर अपनी मिल्कियत समझने वाले दौलतमन्द देशों के माथे पर भी सिलवटें डाल दी। अमेरीका और उसके पिछलग्गुओं ने धरती के तापमान बढ़ने और उसके कारण जलवायु परिवर्तन को 'पर्यावरणीय आतंकवादियों' का दुष्प्रचार बताने वाले देशी–विदेशी नीति–निर्माताओं को भी अब मामले की गम्भीरता नजर आने लगी है। कारण साफ है। सुर्खियाँ कहती हैं कि इस बार ध्रुवों, ग्लेशियरों के पिघलने से तटवर्ती मछुआरों की झोपड़ियाँ ही नहीं बल्कि नरीमन प्वाइंट की बहुमंजिला इमारतों के भी जलप्लावित होने का अन्देशा उत्पन्न हो गया है। डेंगू, मलेरिया और दूसरी संक्रामक बीमारियाँ मलिन बस्तियों की सीमाएँ लाँघ कर आभिजात्य कालोनियों का रुख करने लगी हैं। बीते वर्ष राजधानी दिल्ली में डेंगू ने कई हस्तियों को अपनी चपेट में लेकर अपने इलाके में विस्तार के संकेत दे दिये हैं। इसी तरह पानी बिजली का संकट अब गाँव–कस्बों और छोटे शहरों की चीज नहीं रही, महानगरों की सफेदपोश कालोनियों में संकट कहीं अधिक गहरा हो गया है। कुल मिलाकर उदारीकरण के रथ पर सवार अनियंत्रित उपभोक्तावाद के सूर्य को ग्लोबल वार्मिंग के डरावने बादल ढँकने लगे हैं।

पुस्तकें और दोस्त कम और अच्छे होने चाहिए।

आप तम्बाकू नहीं चबा रहे तम्बाकू आपको चबा रहा है

कपिल सिंघल

तम्बाकू का सेवन किसी न किसी रूप में प्राचीनकाल से चला आ रहा है, पहले लोग तम्बाकू की पत्तियां मसलकर चबाया करते थे। तम्बाकू का सेवन हुक्के के जरिये किया करते थे। चौपाल पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना पुराने समय का फैशन था। लोग तम्बाकू के पत्ते से बीड़ी बनाकर पीते थे। जैसे–जैसे समय निकलता गया, तम्बाकू के सेवन के तरीकों में परिवर्तन भी होता गया। तम्बाकू सेवन के लिए कई उत्पाद बनाए जाने लगे और इससे होने वाली लाखों–करोड़ों की आय को देखते हुए बड़ी–बड़ी कम्पनियां बाजार में आ गयीं। आज तम्बाकू का सेवन पान के साथ, गुटखे के रूप में एवं सिगरेट के रूप में व्यापकता से होने लगा है। तम्बाकू गुटखे, खैनी, सिगरेट के साथ–साथ बीड़ी, जर्दा, किमाम, तम्बाकू वाला पान आदि के रूप में लिया जाता है।

तम्बाकू के प्रचलन ने फैशन का रूप ले लिया है और किशोर उम्र से ही यह व्यसन होठों से लगकर शरीर की आवश्यकता बन जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तम्बाकू चबाने से और सिगरेट पीने से मुंह, फेफड़े, गले, पेट, गुर्दे, मूत्राशय एवं यकृत का कैंसर, जबड़ों का बंद होना, दिल की बीमारी, मसूढ़ों की बीमारी, पैरों में गैगरिन, ब्रेन अटैक, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिल, निमोनिया, उच्च रक्तचाप, लकवा, अवसाद, नपुंसकता, ऊर्जा में कमी आदि क्रॉनिक बीमारियां जन्म ले रही हैं। महिलाओं में तम्बाकू का सेवन गर्भपात और असामान्य बच्चों के जन्म का कारण बनता है। कैंसर के कारणों में तम्बाकू को ए श्रेणी में रखा गया है। तम्बाकू में निकोटिन, नाइट्रोसामाइंस, बैन्जोपाइरीनर्स और क्रोमियम आदि कैंसर पैदा करने वाले प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। 12 से 20 वर्षों तक तम्बाकू का सेवन करने से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

अमेरिकी कैंसर सोसायटी के अनुसार वहां 46 प्रतिशत उपयोगकर्ता 18 वर्ष की आयु में तम्बाकू का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। इन वस्तुओं का सेवन करने वाला इनका आदी हो जाता है तथा बड़ी मुश्किल से इनका सेवन छोड़ पाता है। तथ्य बताते हैं कि पूरे विश्व में 50 से 60 लाख तथा भारत में 10 से 12 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष तम्बाकू से अपने प्राण गंवाते हैं। धूम्रपान करने वालों की आयु 10 से 12 प्रतिशत कम हो जाती है। देश में अगर हम एक वर्ष का आंकड़ा देखें तो वर्ष 2004 में 7700 करोड़ रूपये तम्बाकू उत्पाद पर खर्च किए गए तथा इसी वर्ष 5400 करोड़ रूपये तम्बाकू से जुड़ी बीमारियों पर खर्च किए गए, जो कि सरकार को तम्बाकू से होने वाली राजस्व आय से अधिक है। सिगरेट के धुंए में 4000 से अधिक जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से 60 से अधिक पदार्थ कैंसर कारक हैं। 4 से 5 सिगरेटों में इतना निकोटिन होता है कि यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अकेले भारतवर्ष में 15 करोड़ से अधिक लोग धूम्रपान करते हैं। 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग के 30 प्रतिशत लोग इस कुटेव में जकड़े हैं, जबकि कच्ची उम्र के 13 से 15 वर्ष के 100 बच्चों में से 4 बच्चे इसकी गिरफ्त में हैं। तम्बाकू के प्रयोग में 48 प्रतिशत हिस्सा बीड़ी, 38 प्रतिशत हिस्सा गुटखे का तथा 14 प्रतिशत हिस्सा सिगरेट का है।कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले तम्बाकू के गुटखे का सेवन करते हैं। कई लोग तो दिन भर में कई सौ रूपये का गुटखा गटक जाते हैं। यही नहीं, रात को सोने से पूर्व भी गुटखा गालों में दबा लेते हैं, जो पूरी रात मुंह में सड़ता रहता है। कई जगह तो दांत साफ करने के लिए तम्बाकू के मंजन का प्रचलन है। ऐसे मंजन से महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुड़ी हैं और वे दिन में तीन–चार बार इस मंजन से अपने दांत साफ करती हैं। ऐसे मंजन से दांतों को साफ करने पर उनका एनामल छूट जाता है तथा मसूढ़े भी खराब हो जाते हैं। यह मंजन कई बार पायरिया रोग का कारण बन जाता है। एनामल हटने से दांतों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे ठंडा या गर्म लगने लगता है। दांतों में कैविटी बन जाती है, जिसमें खाद्य पदार्थ फंस जाने से दांतों में सड़न होने लगती है। दांतों की जड़ें बाहर आने लगती हैं, जिससे रूट केनाल की स्थिति बन जाती है। यद्यपि सरकार सिगरेट के पैकेट पर इसके खतरे को देखते हुए सिगरेट नहीं पीने की चेतावनी देती है, परंतु इनका उपयोग कम होने के स्थान पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सिगरेट का धुंआ जब अंदर जाता है तो शरीर में खून को साफ करने वाले फेफड़े काले पड़ने लगते हैं और उनमें टार जमा होने लगता है। अधिक सिगरेट पीने वाले लोगों के फेफड़े का निचोड़ें तो उसमें इतना टार जमा हो जाता है जो कैंसर की बीमारी का कारण बनता है। यही नहीं, तम्बाकू का सेवन करने वालों को पेट का अल्सर जैसी बीमारियां भी घेर लेती हैं।

एक अच्छा पड़ोसी आपके घर की कीमत दोगुनी कर देता है।

आगे बढ़ने की होड़ में इंसानियत को पीछे छोड़ रहा इंसान

नरेंद्र कुमार सक्सेना

इंसानियत यानी मानवता, फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी शहर का हो सबका एकमात्र प्रथम उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनने का होना चाहिए। हर किसी इंसान के रंग रूप, सूरत, शारीरिक बनावट, रहन–सहन, सोच–विचार और भाषा आदि में समानतायें भी होती हैं और असमानताएं भी होती हैं, लेकिन ईश्वर ने हम सभी को पाँच तत्वों से बनाया है। हम सभी में इस परमात्मा का अंश है। आज के इस दौर में इंसान मानवता को छोड़कर, इंसान के द्वारा बनाये गए धर्मों के भेद–भाव के रास्ते पर निकल पड़ा है। इसमें कुछ तो हम लोगों की अपनी सोच है और कुछ राजनेताओं द्वारा रचे प्रपंच है, जोकि राजनीतिक लाभ में भेद–भाव को बढ़ावा देता है। जिसके चलते एक इंसान किसी दूसरे इंसान की ना तो मजबूरी समझता है और ना ही उसकी मदद ही करता है। यहाँ पर इंसानियत पर धर्म की चोट पड़ती है। लोग इंसानियत को छोड़कर अपने ही द्वारा रची गई धर्मों की बेड़ियों में जकड़े जा रहे हैं। इंसान धर्म की आड़ में अपने अंदर पल रहे वैर, निंदा, नफरत, अविश्वास, उन्माद और जातिवादी भेदभाव के कारण अभिमान को प्राथमिकता दे रहा है। जिससे उसके भीतर की मानवता शनैः शनैः दम तोड़ रही है। इंसान प्यार करना भूलता जा रहा है, अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है और तो और अपने परमपिता परमात्मा को भी भूल गया है। इन सबके चलते मानव के मन में दानवता का वास होता जा रहा है। आज धर्म के नाम पर लोग लहू–लुहान करने से पीछे नहीं हटते जिससे संप्रदायों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बीते कुछ समय पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि मुम्बई में हुए तीन बम धमाकों में मानव के भीतर की दानवता का उदहारण दिखा जहाँ कितने ही निर्दोष लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ और परिवार के परिवार उजड़ गए। आज इंसान–इंसान की दुश्मन बनता जा रहा है क्योंकि वो पराये धर्म से है। लोगों का मूल उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो गया है किसी को पैसे का स्वार्थ है तो कोई ओहदे को लेकर और तो कोई एक तरफा प्यार के स्वार्थ में अँधा है। इसी के चलते मानव इंसानियत को अपने जीवन से चलता कर देते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है– श्श्इंसान इंसान को डस रहा है और साँप बैठकर रो रहा है। अब इंसान में हैवानियत–सी आ गई है, उसे अपने अलावा किसी की भी कोई अहमियत नजर नहीं आ रही है। यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि जो इंसान जानवरों और पेड़ पौधों पर भी दया नहीं दिखा सकता वह इंसान पर कैसे कर सकता है ? यही वो इंसान है जो अब सिर्फ श्मैंश शब्द में ही उलझकर रह गया है और इसी में जीना चाहता है। हाल के दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि इंसानियत तार तार हो रही है। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद कि एक घटना जिसमें एक पति तेज गति से गाड़ी चलाते हुए अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था, उसकी रास्ते में टक्कर एक ऑडी कार से होती है जो कि एक महिला चला रही थी। उस टक्कर में उसकी उस कीमती कार पर एक हल्की सी खरोंच आ जाने से वह महिला गुस्से से तमतमा गई और उस दंपत्ति की गाड़ी की चाबी निकाल ली। उस दौरान मानो जैसे उसने अपनी सारी इंसा. नियत को ताक पर रख दिया हो और उसने यह भी नहीं देखा कि एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और उसका पति उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए मिन्नते कर रहा है। यही नहीं ये सब वाकया देख रहे अन्य लोग भी उन लोगों को जाने के लिए बोलते रहे पर उसने किसी की नहीं सुनी। क्या इंसानियत का स्तर इतना गिर गया की एक महिला होकर भी महिला का दुःख नहीं समझ पाई। दया, क्षमा तो महिलाओं के गुण माने जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती इसके अलावा मौत से जूझते हुए एक इन्सान को भी लोगों ने यूँ ही सड़क पर छोड़ दिया मरने के लिए। किसी ने उसकी मदद करनी नहीं चाही। यह जरूर किया कि उस इंसान के दर्द से तड़पने की वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि उस मरते हुए इंसान के साथ साथ मर रही इंसानियत का चेहरा भी देखा जा सके। लोग आज भी यही सोचते हैं कि अगर ऐसी घायल अवस्था में वो किसी को अस्पताल ले जाते हैं तो उनको कानूनी कार्यवाही के झंझट में पड़ना होगा।

मरते थे इंसान कभी पर, अब मर रही है इंसानियत,
पैसे सत्ता और ताकत के लालच में आ गई है, हैवानियत
धर्म और मजहब का ढोल बजा के लहू लुहान किया इंसानों को,
जाति, धर्म का लालच देके झोंक दिया इंसानियत को,
मार दिया उस प्यार को और उसके प्यारे एहसास को,
जप रहा है जाप बस 'मैं' शब्द के नाम को,
दया की भावना तो चली गई, ना ही अपनों का अब दर्द रहा,
देख खुशी दूसरों की आज का इंसान क्यों जल रहा,
कैसा युग है, और क्या समय की मार है, प्यारे
इंसान इंसान को डस रहा और साँप बैठकर रो रहा।।

जिस कार्य से दूसरों का हित होगा, उससे अपना अहित कभी नहीं होगा।

आरडब्ल्यूए सोसायटी के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट

कपिल सिंघल

प्रीत विहार रिहायशी योजना जब बनाई गई थी तो यहां के निवासियों को सुविधा एवं लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए डीडीए ने एक रुपए में क्लब एवं सामुदायिक सुविधाओं के लिए जमीनें दी थीं और यह योजना का ही भाग था। लेकिन जब यह क्षेत्र विकसित हो गया और जमीनें महंगी हो गई तो कुछ परिवार के लोगों ने मिल कर इसे हथियाने की योजना बनाई और आपस में तीन चार परिवार एवं रिश्तेदारों ने एक आरडब्ल्यूए बना ली और उसी आरडब्ल्यूए के माध्यम से बहुमूल्य जमीन को हेराफेरी करके हथिया लिया। इसमें कानूनों को भी ताख पर रख दिया गया और यह परिवार के निजी सम्पत्ति की तरह हो गया। इन लोगों ने सोसायटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए यह प्रस्ताव पास कर लिया गया है एवं प्रमुख पदाधिकारी आजीवन पद पर रहेंगे उसके बाद उनके वारिस उस पद पर बने रहेंगे यानी पैतृक सम्पत्ति की तरह। दूसरा सिर्फ 10 से 15 लेाग इसके सदस्य एवं पदाधिकारी हों जबकि ब्लड रिलेशन में यह नहीं होना चाहिए। क्लब की सदस्यता लाखों में बेच कर अपनी जेब भरी जा रही है। प्रीत विहार के रहने वालों की सहभागिता इसमें है ही नहीं, इस बहुमूल्य जमीन पर शासन एवं प्रशासन की मिलीभगत करके अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है जबकि यह प्रीत विहार के निवा. सियों के लिए है और यह उनका अधिकार है।

इसके लिए सभी प्रीतविहार के लोगों की एक मीटिंग करके आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी का चुनाव होना चाहिए एंव इसकी खाता बही की उचित जांच हो साथ में क्लब में एक मामूली फीस लेकर नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर उसका संच. ालन होना चाहिए किसी एक व्यक्ति की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, आरडब्ल्यूए का संचालन सोसायटी एक्ट 1860 के तहत होना चाहिए न कि एक प्रोपराइटर फर्म की तरह।

'किसान को लागत की भी सब्सिडी नहीं मिलती'

मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने फायरिंग की और कम से कम छह किसानों की मौत हुई और कई आंदोलनक. ारी घायल भी हो गए। महाराष्ट्र में किसान अपनी मांगों को लेकर बीती एक जून से हड़ताल पर हैं। इसके पहले तमिलनाडु के किसान हाथ में खोपड़िया लिए और मुंह में चूहा दबाकर दिल्ली में अर्धनग्न प्रदर्शन कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे होने पर दावा किया कि उसने किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं. नीम कोटेड यूरिया, किसान चौनल और सोइल कार्ड जैसी योजनाओं का कई बार बखान हुआ। लेकिन खेत छोड़कर सड़कों पर उतरे किसानों की आवाज एक अलग कहानी सुना रही है। विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय कृषि ग्रामीण मजदूर महासंघ ने भी केंद्र और राज्य सरकारों की किसान से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. हरित क्रांति के दावे और किसानों के दिन बदलने के वादों के बीच किसानों, उनके बीच काम करने वालों और कृषि विशेषज्ञों समेत सभी की राय है कि खेती करने वालों के सामने हालात दिन–ब–दिन मुश्किल होते जा रहे हैं।

साभार : इंटरनेट

सिस्टम दुरुस्त तो सब दुरुस्त

अश्विनी मिश्रा

जरा सोचिए कि जिस देश में समाज में 95 फीसद संस्थाएं भ्रष्टाचारी हों उस देश व समाज में कौन सा कानून एवं मानव मूल्यों, सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा। भीड़ एवं जनता का स्वभाव एक तरह होता है, हां कुछ जरुर कहीं–कहीं अंतर है किंतु व्यवस्था एंव मानव मूल्यों के आधार पर बहुत कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जैसे इसका सहीं उदाहरण दिल्ली मेट्रो है यहां व्यवस्था ऐसी है हर व्यक्ति अनुशसित होकर यात्रा करता है वहीं बाहर निकलते ही अपने पुराने स्वभाव में आ जाता है, उ.प्र. से गाड़ी जैसे दिल्ली में जाती है तथा ट्रैफिक नियमों का पालन खुद करने लगते हैं। यह कुछ उदाहरण है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था ठीक की जाए तो लोग उसे मानने के लिए तैयार हैं कानून पालन करे के लिए तैयार पर पालन कराने वाले ही कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ भी कहा जाए कम है एवं उसके सम्मान में ठेंस पहुंचती है। हमारे देश में आम जनता को जो मेरे सोच के हिसाब से सबसे बड़ा हथियार दिया गया है वह है जन सूचना का अधिकार 2005 लेकिन इसी से अब तक सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग का काम हो रहा है।

कुसंगति व्यक्ति विनाश कर देती है।

वादे हैं वादों का क्या!

प्रमोद कुमार सिंह (एडवोकेट)

नेपोलियन बोनापार्ट और अडॉल्फ हिटलर ने सत्ता की चाहत में अपना पूरा पक्ष बदल दिया, पर वे व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के दाग से मुक्त रहे। नेपोलियन ने फ्रांस को पहला गणतांत्रिक संविधान दिया। लेकिन वह जैसे ही शक्तिशाली हुआ उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। हिटलर सभी समकालीन नेताओं तथा राजनीतिक दलों को भ्रष्ट और निकम्मा बता कर सत्ता में आया, लेकिन एक बार निर्वाचित होने के बाद उसने अपनी नात्शी पार्टी को अधिनायकवादी तरीके से चलाया।

केजरीवाल ने शुरू में राजनीतिक शैली बदलने पर जोर दिया तो उसका एक महत्वपूर्ण तत्व था आलाकमान की संस्कृति को खत्म कर निर्णय लेने में कार्यकर्ताओं की सहभागिता। विडंबना यह है कि वही केजरीवाल सबसे बड़े आलाकमान हो गए, जिनकी मर्जी के बिना पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अपने घोषित पक्ष को पलटते हुए कि वह स्वयं कभी कोई पद नहीं लेंगे, उन्होंने चुनाव होते ही मुख्यमंत्री का पद थाम लिया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का पद अपने पास रखकर एक–व्यक्ति, एक–पद के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी। उन्होंने वह सब किया, जिसके खिलाफ बोले। अपने बच्चों की कसम खाई कि कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे, किंतु ठीक ऐसा ही किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का सफाया हो गया तो वह दोबारा सरकार बनाने के लिए बेचैन हो गए और जोड़–तोड़ में लग गए। हरियाणा चुनाव जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनाव करा दिया और केजरीवाल की किस्मत दोबारा खुल गई। केजरीवाल ने सरकार बनते ही शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजने का वादा किया था, लेकिन आज तक उनके विरुद्ध एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। वीपी• सिंह ने भी सत्ता में आने के 15 दिनों के अंदर बोफोर्स के गुनहगारों को दंडित करने का वादा किया था पर पीएम बनने के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह वीपी• सिंह ने ईमानदारी का इस्तेमाल रणनीति के तौर पर किया।

केजरीवाल के लिए भी ईमानदारी एक रणनीति है। ईमानदारी हो या अन्ना हजारे, केजरीवाल सबका इस्तेमाल फायदे के लिए करते हैं और मतलब सधने के बाद उन्हें छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। आज अन्ना का उनसे मोहभंग हो चुका है। उन्हें अहसास है कि उनका इस्तेमाल किया गया सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए।

उनका यह बयान स्वागत योग्य है कि यदि आरोप प्रमाणित हुए तो वह अरविंद के विरुद्ध जंतर–मंतर पर अनशन करेंगे अतीत में भी कई भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुए हैं। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन मूलतः भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, मगर आपातकाल थोपे जाने के बाद वह लोकतंत्र को बचाने वाला आंदोलन हो गया। वीपी सिंह का अभियान भी करप्शन के खिलाफ था। अन्ना आंदोलन अल्पकालिक रहा क्योंकि उनके पास गांधी या जयप्रकाश वाली दृष्टि नहीं है, हालांकि उनकी ईमानदारी निर्विवाद है। केजरीवाल एक स्वंयभू समाज सुधारक से एक कट्टर राजनेता बन चुके हैं। वह सफल हैं। सफलता को दुनिया पूजती है। किंतु इतिहास उन्हें इस बात के लिए माफ नहीं करेगा कि उन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति की संभावना को लंबे समय के लिए खत्म कर दिया। केजरीवाल के संदर्भ में ईमानदारी को अब सिर्फ एक रणनीति समझा जा रहा है।

झूठ छिपाने से नहीं छिपता।

आंकड़े बता रहे अच्छे दिन के संकेत

कमलकांत त्रिपाठी :– आजादी के 70 साल बीत रहे हैं। देश ने अनेक सरकारों को देखा है। आम जनता को सभी केन्द्रीय सरकारों के खट्टे–मीठे अनुभव प्राप्त हुए हैं। एक समय था जब विपक्ष सोच भी नहीं सकता था कि वह राष्टीय स्तर पर सत्तासीन हो सकेगा, लेकिन लंबे समय तक विपक्ष में रहने वाली पार्टी को जनता–जनार्दन ने अधिकांश राज्यों सहित केंद्र में भी व्यापक जनसमर्थन दिया है। प्रतिकूलता में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है और अनुकूलता में मर्यादा और विनम्रता की आवश्यकता होती है। 16 मई और 26 मई 2014– यह तिथि भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। भारतीय राजनीति और भारत की सरकार को स्थायित्व देने का सुनहरा समय प्रारंभ हुआ। समय किसी का सहोदर नहीं होता है। वह तो आता है और चला जाता है। आज जब हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीन वर्षों के कार्यों और भाजपा के राष्टीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यों का अवलोकन करते हैं तो लगता है कि मोदी सरकार आध्यात्मिक समाज के भगवान श्रीराम की मर्यादाओं से बंधकर जनहितार्थ कार्य करने में लगे हुए हैं और वहीं राष्टीय अध्यक्ष अमित शाह भगवान श्रीकृष्ण के पथ पर चलकर नयी राजनीति से दल का विस्तार करते हुए परिणाम तक ले जाने में जुटे हुए हैं। वर्षों से भाजपा पर अगड़ों और अमीरों की पार्टी होने का ग्रहण लगता रहा। मोदी सरकार और भाजपा संगठन ने पिछले तीन वर्षों में इस मिथक को तोड़ते हुए हर गरीब के घर–घर में यह बात पहुंचाने का सफलतम प्रयास किया है कि मोदी सरकार और भाजपा संगठन गरीबों की पार्टी है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली पार्टी है। 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे आजादी के बाद कांग्रेस देती रही, लेकिन गरीबी हटी नहीं। भाजपा ने न नारा दिया, न वादा किया। प्रधानमंत्री ने संसद की चौखट पर माथा टेकते हुए पहला वाक्य कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। और अपने पहले वाक्य को अभी तक जमीन पर साकार करने के लिए मोदी सरकार का हर फैसला साकार होता दिख रहा है। भारतीय समाज को पहली बार यह अहसास हो रहा है कि निर्वाचित सरकार हमारी है। सरकार की सफलता पहले पायदान पर उस समय समझ में आती है कि जब समाज यह कहने लगे कि जो हम सोच रहे हैं वही सरकार कर रही है। देश भ्रष्टाचार से त्रस्त था। घोटालों की गूंज से संसद गूंजती रहती थी। आम आदमी का जीवन भ्रष्टाचार के कारण त्रस्त हो गया था। तीन साल में कालेधन पर रोक, भ्रष्टाचार से मुक्ति और बेनामी संपत्ति पर अलीगढ़ का ताला लगाने का जो सफलतम प्रयास मोदी सरकार ने किया है वह हर जुबां पर है। कालेधन से मुक्ति के लिए विमुद्रीकरण का ऐतिहासिक फैसला किया गया। विमुद्रीकरण की परीक्षा में नरेन्द्र मोदी जहां शत–प्रतिशत सफल हुए हैं, वहीं गरीबों ने अपनी आवाज से सरकार के साथ आवाज मिलाकर दो–टूक लोकतांत्रिक फैसला दिया कि विमुद्रीकरण पर मोदी सरकार के साथ हैं। इतना कठोर निर्णय! गरीब से गरीब को कठिनाई हुई, लेकिन सबके मन में एक खुशी थी कि कालाधन और भ्रष्टाचार रोकने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। विपक्षी पूछते हैं कि सरकार ने क्या किया? तीन साल में 49 करोड़ लोगों से अधिक को सीधा लाभ पहुंचाने और उनके सिर्फ बैंक खाते ही नहीं, बल्कि तकदीर के खाते खोलने का काम किया है। कुछ आंकड़े– जनधन–योजना के तहत 27.97 करोड़ खाते खोले गए। इन खातों में इन गरीबों ने स्वयं 63.835 करोड़ रुपए जमा किए। अब इन खातों में सरकारी योजनाओं की राशि जाने लगी। 13 करोड़ गरीबों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया गया। स्टार्टअप एवं स्टैण्डअप योजना के तहत मुद्रा योजना के माध्यम से 6.6 करोड़ लोगों ने ऋण लिये और व्यापार शुरू किया। उज्ज्वला योजना के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति जैसे 2 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। यह उज्ज्वला यही नहीं थमेगी, आने वाले वर्षों में 5 करोड़ लोगों के घर में धुआं बंद करेगी। क्या किया तीन साल में, विपक्षी पूछते हैं? राष्टंपिता महात्मा गांधी के बाद स्वच्छ भारत को अगर किसी ने जनांदोलन बनाया तो वह नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है। स्वच्छता, समाज को स्वस्थता की ओर ले जा रही है।

पतिव्रता नारी गरीब से गरीब घर को स्वर्ग बना देती है।

बॉलीवुड की अभिनेत्रियां जिन्होंने प्यार के लिए अपना धर्म छोड़ दिया...

प्यार किसी भी धर्म, किसी भी जाति को नहीं देखता... प्यार तो सिर्फ प्यार होता है. जब आप प्रेम में हैं तो धर्म और जाति का कोई फर्क नहीं पड़ता. जब प्रेम को विवाह के सूत्र में बदलने की बात आती है, तो कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के उदाहरण सामने हैं जिन्होंने प्यार के लिए अपना धर्म बदल दिया. कुछ बॉलीवुड के प्रसिद्ध जोड़ों की बात करते हैं जिन्होंने अपना धर्म प्यार के लिए बदल दिया।

शर्मिला टैगोर ने एक बंगाली फिल्म अभिनेत्री के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था. उन्होंने मंसूर अली खान पटौदी से शादी की जो कि नवाब थे और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे. 27 दिसंबर 1969 को उनके निकाह समारोह का आयोजन किया गया था. शर्मिला ने इस्लाम अपना लिया और उनका नाम बेगम आयशा सुल्ताना रखा गया. मंसूर अली खान का शादी के 41 साल बाद 70 साल की उम्र में 22 सितंबर 2011 को निधन हो गया.

अमृता सिंह सिख धर्म से थीं. जब उनका और सैफ अली खान का इश्क परवान चढ़ा तो सवाल धर्म का उठा. सैफ अली खान से शादी करने के लिए अमृता ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया. उन्हें इसके बावजूद सैफ अली खान के माता–पिता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें अमृता पसंद नहीं थी. सैफ अली खान के साथ अमृता की शादी 13 साल चली, जिसके बाद दोनों में तलाक हो गया।

आयशा एक हिंदू पिता और एक एंग्लो–इंडियन मां की बेटी हैं. आयशा टाकिया ने अपने प्रेमी रेस्तरां के मालिक फरहान आजमी से शादी की. उनका निकाह समारोह ठेठ इस्लामी था. आयशा के धर्म परिवर्तन की बात कभी भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई, हालांकि विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि उसने फरहान से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया है।

नरगिस दत्त ने प्यार होने पर अपने धर्म को आड़े नहीं आने दिया. नरगिस ने अभिनेता सुनील दत्त से शादी की और मुस्लिम से हिंदू हो गईं. उन्होंने अपना नाम भी निर्मला दत्त रख लिया. इस जोड़े ने 11 मार्च 1958 को शादी की. इनके तीन बच्चे संजय, नम्रता और प्रिया हैं. अब यह जोड़ा इस दुनिया में नहीं है.

दक्षिण भारतीय अभिनेत्री नगमा तेलुगू और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस के रूप में ज्यादा बेहतर जानी जाती हैं. एक हिंदू होने के बावजूद उन्होंने प्यार के कारण ईसाई धर्म अपना लिया. उन्होंने प्यार किया जीजस क्राइस्ट से. एक साक्षात्कार में एक बार उन्होंने कहा, ईसा मसीह उनके अपने जीवन में एकमात्र सुपरस्टार थे. वह प्रचार करना चाहते थे और हर शहर में सुसमाच. ार फैलाना चाहते थे। साभार : इंटरनेट

पिता ने बेटी की हत्या कर फेसबुक पर किया वायरल

किसी भी बेटी का पिता के प्रति मां की अपेक्षा ज्यादा लगाव होता है. अक्सर पिता और बेटी में आपस में ज्यादा लगाव होता है. थाईलैंड के एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया है, जिसके बारे में जानकर किसी का भी रुह कांप जाए. यहां के 21 वर्षीय शख्स ने अपनी बेटी की हत्या कर दी. उस शख्स ने बेटी को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या की. न्यूज एजेंसी रायटर के मुताबिक पत्नी से झगड़े के बाद थाईलैंड के इस शख्स ने होटल में ही बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया. इतना ही नहीं, बेटी की हत्या के बाद शख्स खुद भी खुदकुशी फांसी पर लटक गया. उसने बेटी की हत्या का फेसबुक लाइव भी किया, जिसके चलते परिवार के सारे लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख तो रहे थे, पर वे चाहकर भी नहीं रोक पाए। पिता ने थाईलैंड के फुकेट होटल में इस वारदात को अंजाम दिया. वीडियो के मुताबिक शख्स पहले अपनी बेटी के गले में रस्सी बांधता है और उसे छत से लटका देता है. बेटी की जबतक मौत नहीं हो जाती है उसे लटकाए रहता है. उसके बाद वह रस्सी ऊपर खींचता है और बेटी के शव को अलग करता है. फेसबुक पर वीडियो देखकर उस शख्स के परिवार और दोस्त पुलिस को सूचना देते हैं और घटनास्थल की ओर रवाना होते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. फेसबुक पर यह वीडियो आने के बाद यूजर्स की ओर से लगातार शिकायतें आने लगी. इसके बाद आनन–फानन में फेसबुक ने तत्काल इसे हटा दिया. फेसबुक की ओर से जारी बयान में कहा गया है, श्यह एक दिल दहलाने वाला वीडियो है. पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं. सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर ऐसे वीडियो के लिए कोई जगह नहीं है. इसलिए हटा दिया गया है. फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने आश्वासन दिया है कि वे कंपनी पूरी कोशिश में जुटी है कि आगे से फेसबुक पर ऐसे वीडियो न अपलोड किए जा सकें। साभार : इंटरनेट

जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं।

गोण्डा जिले से चार मंत्री फिर भी शहर गंदा

सच्चिदानंद मिश्र

अभी हुए स्वच्छता सर्वे में गोण्डा ने सबसे गंदे शहर की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि गोण्डा से केंद्र व राज्य से चार मंत्री इसी जिले से हैं। स्वच्छ भारत का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया जो गुजरात के मुंख्यमंत्री भी रहे हैं। स्वामी नारायण जी की जन्मस्थली गोण्डा ही है। गुजराती भगवान मानते हैं। अभी हाल में प्रधानमत्री द्वारा अक्षर धाम मंदिर दिल्ली में जर्मन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ दौरा करके वहां की भव्यता एवं सुंदरता का गुणगान किया था। अक्षरधान मंदिर का नाम गीनिज बुक के रिकार्ड में भी दर्ज है लेकिन उन्हीं भगवान के जन्म स्थली का यह बुरा हाल है। अगर ब्लाक स्तर पर सर्वे कराया जाए तो गोण्डा जिले का छपिया ब्लाक की स्थिति और भी खराब है। यहां 17वीं शताब्दी के गांव हैं जहां आज तक न तो बिजली है और न ही सड़क। इस लोक जागृति संस्था एवं उसकी मासिक पत्रिका की ओर हम प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री एवं सभी अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि गोण्डा का छपिया पर्यटक स्थल के रुप में विकसित किया जा सकता है, श्री स्वामीनारायण के मंदिर देश एवं विदेशों में बने हुए हैं लेकिन उनके जन्म स्थली को विकसित करने का सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है और न ही इस स्वामीनारायण के प्रबंधन द्वाराजबकि हमारे द्वारा बात करने पर पता चला है कि स्वामीनारायण के ऐतिहासि धरोहर के रखरखाव व प्रचार–प्रसार में पैसे की कोई कमी नहीं है साथ में इस काम की जिम्मेदार स्वामीनारायण के खानदान के लेागों को दी गई है। अक्षरधाम के बारे में लोग जानते हैं लेकिन स्वामीनारायण एंव उनके जन्मस्थान छपिया (गोण्डा) के बारे में छपिया के लोगों को ही नहीं पता है।

जंगलराज

हरिशंकर यादव

गोण्डा एवं बस्ती दोनों के बार्डर पर बसा बभनान कस्बे में किसी सरकार का राज न होकर जंगलराज है क्योंकि दो जिलों में बंटा होने के कारण अपराधी आसानी से अपराध करके एक जिले से दूसरें जिले में प्रवेश कर जाते हें जिससे उन्हें पुलिस क्षेत्राधिकार के कारण प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाती है। शहर का विकास कार्य भी दो जिले होने की वजह से एक समान रुप से नहीं हो पाता है। साथ में यहां पर सड़कों पर अतिक्रमण इतना हो रखा है कि अंदर पैदल चलना मुश्किल हो गया है, अवैध मेडिकल स्टोर, एंव लैब की भरमार है, 10वीं फेल लोग लैब का संचालन कर हे हैं, फर्जी दवाओं, एवं झोलाछाप डाक्टरों की भरमार है जिसके कारण ग्रामीणों को जान तक गंवानी पड़ रही है। बाकी बची कसर बलरामपुर शुगर मिल की बभनान ईकाई पूरा कर देती है पूरे शहर को गंदगी, प्रदूषण एवं गन्ने से लदे ट्रक, ट्रॉली ने पूरा कर दिया है। कई शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाई नहीं होती है और जो कुछ होती भी है तो वह दो जिले में बंटा होने से प्रभावी नहीं हो पाती है। साथ में यहां छुटभैया नेताओं द्वारा व्यापारियों से अवैध वसूली का धंधा भी चलता रहता है। गोण्डा एवं बस्ती के बीच यह एक ऐसा कस्बा है जहां विद्यालय, महाविद्यालय, शुगर मिल, रेलवे स्टेशन हैं और काफी संख्या में गांवों से जुड़ा होने के कारण बभनान को पूर्वांचल का बॉम्बे कहा जाता है लेकिन अव्यवस्था एवं जंगलराज के कारण अपनी बेहाल बदहाली के लिए मजबूर है।

प्रदूषण एवं रासायनिक कचरा फैलाती बभनान की बलरामपुर चीनी मिल।

Royal Offset

Printing The World With Quality

011-65253662,63,64,66, 9971859595, 9999566724
Email Id:-royaloffset207@gmail.com
489 F.I.E, Patparganj Delhi-110095

HEIDELBERG S.M. 74
20x30

NEW BRAND MACHINE
24 घंटे में 200 सैट

KOMORI
19x26

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है।यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।
- लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन।
- लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना।
- गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना।
- अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना।
- लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना।
- धार्मिक जागरुकता फैलाना।

संतोष कुमार मिश्रा
अधिवक्ता

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
मोबाइल : 9810960818 ई–मेल : lokjagriti@gmail.com, www.lokjagriti.com

RNI NO.UPHIN/2011/39809

DPL BUILDERS PVT. LTD

Present's

DPL FLORA HERITAGE
24 carat lifestyle

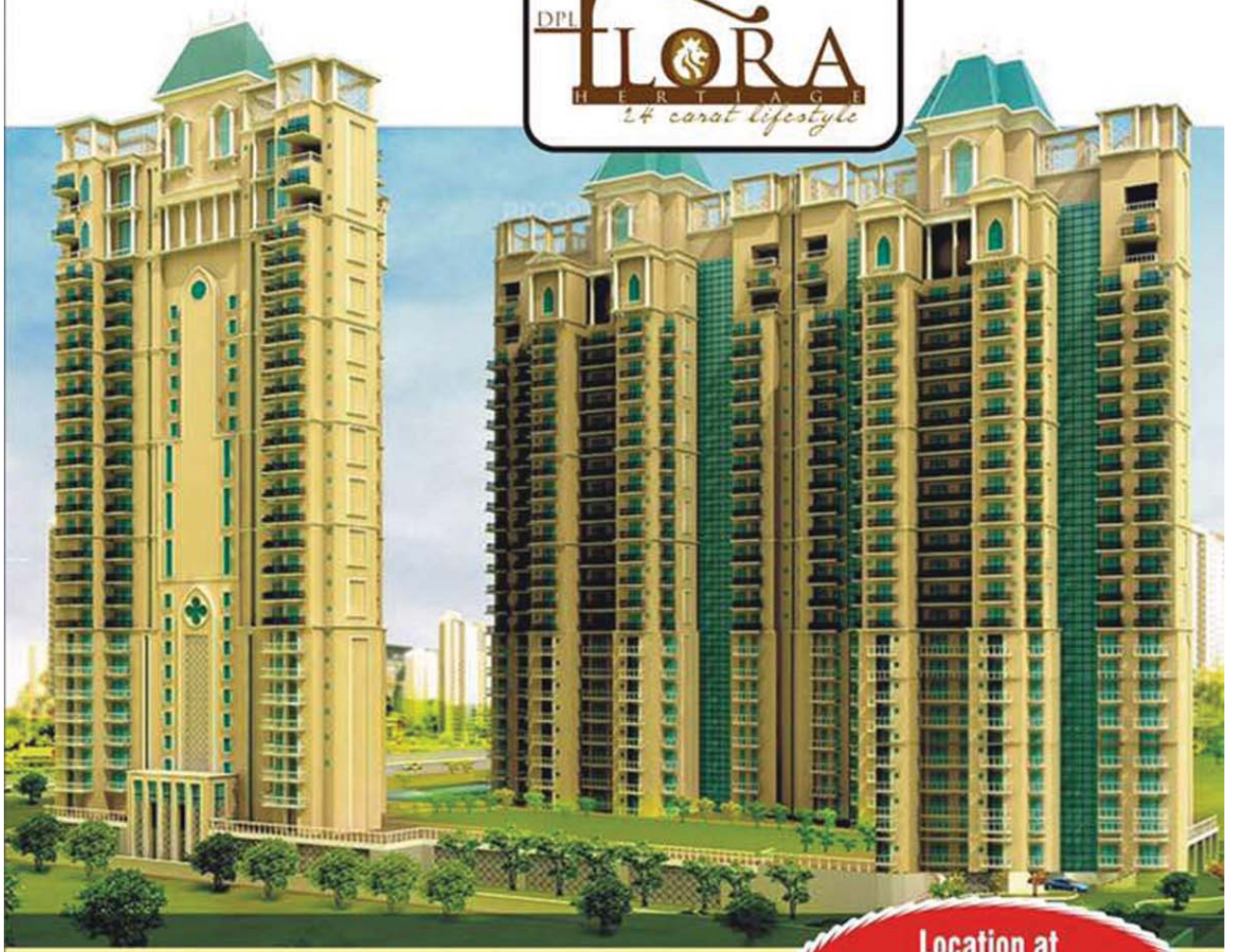

Location at
Greater Noida West, Sector-1
Near Balak Inter College

We Bring Ideas To Reality :

- Roman & Gothic Architecture/ Three Side Open Apartments.
- Podium Heights structure with Double Height entrance lobby.
- Balconies & Windows in all Rooms/ Best Contruction Quality and Best in Architectural Layout.

Location Advantage :

- 0 Km Distance from Market, Banks, Petrol Pump, IT Parks, Malls etc.
- 10 Minutes distance from Metro Station Sector-78.
- 30 Minutes drive to Faridabad, Ghaziabad or Gurgaon through FNG Road.
- Adjacent to Balak Inter College/ Green Belt & Laxurious Farms.
- Adjoining 75 Mtr. Main Commercial Belt.

For Site Visit Contact : A. Sinha +91-7840023993, +91-9818500547

Marketing office : **DPL BUILDERS PVT. LTD** | B-153, Sector-63, Noida